राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक
तरुणमित्र
श्रम ही आधार, खबरों से सरोकार

भोपाल
वर्ष: 6 अंक 111
मंगलवार 9 जून, 2026

तापमान
अधिकतम 42°C
न्यूनतम 29°C

www.youtube.com/@TarunmitraGroup

मूल्य 2 रुपए
पृष्ठ-8

मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र से प्रकाशित

www.tarunmitra.in

ईरान-इजरायल तनाव बढ़ा भारत ने जारी की नई एडवाइजरी

- ईरान में फंसे भारतीयों से जल्द देश छोड़ने की अपील
- बढ़ते सैन्य संघर्ष के बीच यात्रा टालने की सलाह

नई दिल्ली, 08 जून। ईरान और इजरायल के बीच फिर भड़के सैन्य संघर्ष के बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। ईरान में भारतीय दूतावास ने सभी भारतीयों को फिलहाल ईरान की यात्रा से बचने की सलाह दी है। साथ ही वहां मौजूद भारतीय नागरिकों से उपलब्ध परिवहन साधनों का उपयोग कर जल्द से जल्द देश छोड़ने को कहा गया है। दूतावास ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी संदेश में कहा कि क्षेत्र में तेजी से बदलते सुरक्षा हालात को देखते हुए पहले जारी परामर्श को दोहराया जा रहा है।

भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की भी सलाह दी गई है। इस बीच ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएनए के अनुसार, तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं, जबकि ईरान के पश्चिमी हवाई क्षेत्र को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। दूसरी ओर इजरायल ने भी तेल अवीव स्थित बेन गुरियन हवाई अड्डे पर सुरक्षा प्रतिबंध और कड़े कर दिए हैं। तनाव उस समय और बढ़ गया जब लेबनान में हिज्बुल्लाह पर इजरायली कार्रवाई के जवाब में ईरान ने रविवार रात इजरायल के कई क्षेत्रों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं।

जवाबी कार्रवाई में इजरायल ने ईरान के खुजेस्तान प्रांत स्थित माहशहर क्षेत्र की कारून पेट्रोकेमिकल कंपनी समेत कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया।

भारत बन रहा ग्लोबल फार्मा हब : मोहन यादव

मप्र के पीथमपुर में बनेगी हेलियन ग्रुप की पहली मैन्युफेक्क्ररिंग यूनिट, मुख्यमंत्री ने वीसी से किया यूनिट का भूमि-पूजन

भोपाल, 08 जून। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज पूरी दुनिया में 'फामेर्सी ऑफ द वर्ल्ड' के रूप में अपनी सशक्त पहचान बना चुका है। वर्तमान में दुनिया भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में ही नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद उत्पादन केंद्र, वैश्विक सप्लाई चेन पार्टनर और आर्थिक महाशक्ति के रूप में भी देख रही है। भारत को 'ग्लोबल फार्मा हब' बनाने में मध्य प्रदेश की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को पीथमपुर में स्थापित होने जा रही विश्व की अग्रणी कंज्यूमर हेल्थकेयर कंपनी हेलियन ग्रुप की देश में पहली मैन्युफैक्क्ररिंग यूनिट के भूमि-पूजन समारोह (वर्चुअल ग्राउंडब्रेकिंग सेरेमनी) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर कंपनी की नई मैन्युफेक्क्ररिंग यूनिट का सांकेतिक भूमि-पूजन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश आज हर क्षेत्र में निवेश के नये युग में प्रवेश कर

आर्थिक एवं औद्योगिक विकास का नया अध्याय लिख रहा है। हेलियन कंपनी ने भारत में पहली मैन्युफेक्क्ररिंग यूनिट के लिए मध्य प्रदेश के पीथमपुर को चुना है। मध्य प्रदेश की भूमि सफलता की धरती भी है। मध्य प्रदेश सरकार और हेलियन कंपनी के बीच आज परस्पर विश्वास की और असीम संभावनाओं की नई शुरूआत हो रही है। हमारी औद्योगिक नीतियों के कारण देश-दुनिया सभी मध्य प्रदेश पर भरोसा कर रहे है। सबका यही विश्वास ही हमारी पूंजी है।

दो हजार करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित हो रही इस यूनिट से एक हजार लोगों को मिलेगा रोजगार : मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नए दौर का मध्य प्रदेश है। हमारा प्रदेश अब आत्मनिर्भर बन रहा है। मध्य प्रदेश में निवेश के इच्छुक सभी निवेशकों को उद्योग स्थापना से लेकर उत्पादन प्रारंभ होने तक हर स्तर पर राज्य सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा।

बताया गया कि कंपनी ने मध्य प्रदेश में तात्कालिक तौर पर 2 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया है। इस मैन्युफैक्क्ररिंग यूनिट के माध्यम से करीब 1000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने इस ऐतिहासिक भूमि-पूजन अवसर पर हेलियन ग्रुप को बधाई देते हुए कहा कि सरकार हर कदम पर आपके सहयोग के लिए साथ खड़ी है।

उन्होंने हेलियन कंपनी सहित अन्य निवेशकों का मध्य प्रदेश में स्वागत करते हुए उन्हें बिना किसी संकोच के खुले हृदय से मप्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत मात्रा के आधार पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मा उत्पादक देश है। यहां 3 हजार से अधिक कम्पनियां और 10 हजार 500 से अधिक विनिर्माण इकाइयां दवाओं का उत्पादन कर रही हैं।

मध्य प्रदेश में 300 से अधिक फार्मा कम्पनियां तथा 30 से अधिक एपीआई और बल्क ड्रग्स निमार्ता सक्रिय हैं। इनके द्वारा निर्मित दवाएं अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में निर्यात हो रही हैं। मध्य प्रदेश में 75 से अधिक मेडिकल डिवाइस यूनिट्स सक्रिय हैं। राज्य के कुल निर्यात में फार्मा सेक्टर का लगभग 20 प्रतिशत योगदान है।

मध्य प्रदेश अब केवल उत्पादन केंद्र नहीं, बल्कि एक स्थापित ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बन चुका है। प्रदेश में इंदौर, पीथमपुर, मंडीदीप, भोपाल, देवास और उज्जैन के औद्योगिक क्षेत्र फार्मा मैनुफैक्क्ररिंग क्लस्टर्स के रूप में विकसित हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 में यूनाइटेड किंगडम (यूके) में हुए 'इन्वेस्ट इन एमपी रोड शो' के दौरान बोया गया निवेश का बीज आज पीथमपुर में अपना वास्तविक स्वरूप ले रहा है।

संक्षिप्त समाचार

इंदौर में आज से शुरू होगी ब्रिक्स देशों की बैठक

भोपाल, 08 जून (हि.स.)। मध्य प्रदेश के इंदौर में मंगलवार, 09 जून से ब्रिक्स देशों के एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप एवं कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो रही है। आगामी 13 जून तक चलने वाली इस बैठक में 20 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारत इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए आयोजन को लेकर विस्तृत रुपरेखा साझा की।

तृणमूल सांसद सुखेंद ने छोड़ी पार्टी, सांसद पद से भी दिया इस्तीफा

कोलकाता/नई दिल्ली, 08 जून। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के साथ-साथ राज्यसभा की सदस्यता भी छोड़ दी है। सोमवार सुबह दिल्ली से उन्होंने पार्टी छोड़ने की घोषणा की और आरजी कर अस्पताल की चर्चित घटना तथा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पार्टी नेतृत्व के खिलाफ खुलकर नाराजगी जताई। सुखेंदु शेखर राय ने दावा किया कि उन्होंने आरजी कर प्रकरण के बाद ही पार्टी छोड़ने का निर्णय ले लिया था, जिसे अब अमल में लाया गया है।

राष्ट्रपति 23 जून को 65 प्रतिष्ठित लोगों को प्रदान करेंगी पद्म पुरस्कार

नई दिल्ली, 08 जून। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 23 जून को राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के 65 प्रतिष्ठित लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति ने इससे पूर्व 25 मई को पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री पुरस्कार शामिल थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने पांच पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी थी।

पिता ने तीन बेटियों की धारदार हथियार से की हत्या, गिरफ्तार

गिरिडीह, 08 जून। गिरिडीह जिले में सोमवार तड़के एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां तुरुकडीहा निवासी नंदू यादव उर्फ नंदकिशोर यादव ने सोमवार की अहले सुबह अपनी तीनों बेटियों पर हंसुआ से हमला कर दिया। इस हमले में 14 वर्षीय पल्लवी यादव और सात वर्षीय जुड़वां बहनें रिद्धि एवं सिद्धि की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हत्यारोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

भारत ने पश्चिम एशिया में सभी पक्षों से तनाव कम करने का किया आग्रह

नई दिल्ली, 08 जून। पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य संघर्ष को देखते हुए भारत ने सभी पक्षों से तनाव कम करने और नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह किया है। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में सभी पक्षों से आग्रह किया कि वह तनाव को कम करने, नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने और राजनयिक समाधान तलाशने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाएं।

एआईसीसी सचिव सूरज हेगड़े के निधन से कांग्रेस को बड़ा झटका

नई दिल्ली, 08 जून। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस सचिव एवं भारतीय युवा कांग्रेस के पूर्व प्रभारी सूरज हेगड़े के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

दोनों नेताओं ने उनके निधन को कांग्रेस परिवार के लिए अपूरणीय क्षति बताते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की। मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा कि सूरज हेगड़े के असामयिक निधन से उन्हें गहरा सदमा और दुख पहुंचा है। उन्होंने कहा कि हेगड़े एक युवा, ऊजार्वान और होनहार नेता थे, जिन्होंने कांग्रेस सचिव के रूप में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ संगठन की सेवा की। खड़गे ने कहा कि वह

सूरज हेगड़े को उनके किशोरावस्था के दिनों से जानते थे और उन्हें संगठन के प्रति पूरी तरह समर्पित नेता के रूप में आगे बढ़ते देखना सुखद अनुभव रहा। वहीं राहुल गांधी ने भी शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सूरज हेगड़े के निधन से उन्हें गहरा दुख हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सचिव और भारतीय युवा कांग्रेस के पूर्व प्रभारी के रूप में हेगड़े ने पार्टी के आदर्शों और विचारधारा के प्रति गहरी आस्था के साथ काम किया।

विपक्षी एकजुटता की नई हुंकार, सरकार पर प्रहार

नई दिल्ली 08 जून। आगामी राजनीतिक चुनौतियों तथा संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष की साझा रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से सोमवार को दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन की सातवीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में 25 विपक्षी दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) की सुप्रिया सुले, राजद नेता तेजस्वी यादव, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, कपिल सिब्बल समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जबकि शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

दो घंटे से अधिक समय तक चली बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बताया कि गठबंधन पांच प्रमुख मुद्दों पर सहमत हुआ है और इन विषयों पर संयुक्त रूप से संघर्ष करेगा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का गठन

बैठक

- हर दो महीने में होगी बैठक, अगस्त में हैदराबाद अगला पड़ाव
- नीट-सीबीएसई विवाद पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग
- मतदाता सूची और चुनावी निष्पक्षता पर सीजेआई को भेजेंगे पत्र

लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा के उद्देश्य से हुआ था तथा वर्तमान परिस्थितियों में इसकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है।

उन्होंने हाल में परिसीमन से जुड़े मुद्दे पर विपक्षी दलों की एकजुटता का उल्लेख करते हुए कहा कि जब विपक्ष साथ खड़ा होता है तो उसकी आवाज अधिक प्रभावी बनती है।

बैठक में चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता, मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। गठबंधन ने चुनावों में निष्पक्षता और कथित वोट चोरी के मामलों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजने का निर्णय लिया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जाना आवश्यक है। शिक्षा और युवाओं से जुड़े विषय भी बैठक के केंद्र में रहे। नीट-यूजी और सीबीएसई परीक्षाओं से जुड़े विवादों का उल्लेख करते हुए गठबंधन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की।

आंधी-बारिश में आईजीआई पर एयर इंडिया के तीन विमान क्षतिग्रस्त

नई दिल्ली, 08 जून। राजधानी दिल्ली में रविवार को आई तेज बारिश और आंधी का असर देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे पर भी देखने को मिला। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआई) पर पार्क किए गए एयर इंडिया के तीन विमान उस समय क्षतिग्रस्त हो गए, जब तेज हवाओं के कारण ग्राउंड सपोर्ट उपकरण अपनी जगह से खिसककर विमानों से टकरा गए। घटना के बाद संबंधित विमानों को एहतियातन परिचालन से बाहर कर दिया गया है और उनकी तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल) के अनुसार, यह घटना टर्मिनल-2 पर हुई, जहां खराब मौसम के बीच ग्राउंड हैंडलिंग उपकरण नियंत्रण से बाहर होकर एयर इंडिया के तीन नैरो-बॉडी विमानों से जा टकराए।

12 साल में भारत ने देखे बड़े परिवर्तन: प्रधानमंत्री

नई दिल्ली, 08 जून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में अपनी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश की विकास यात्रा और जनकल्याणकारी उपलब्धियों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि इस पूरे कार्यकाल में सरकार का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना रहा है और इसी सोच ने नीति निर्माण की दिशा तय की है।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर साझा संदेशों में कहा कि उनकी सरकार 'अंत्योदय' के सिद्धांत से प्रेरित रही है, जिसके तहत लंबे समय से

संबोधन

- मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे, विकास और गरीब कल्याण पर जोर

वंचित और हाशिए पर खड़े वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि विकास का लाभ अब सीधे जनता तक पहुंच रहा है और इसके परिणामस्वरूप सामाजिक-आर्थिक स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। उन्होंने जनधन योजना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन कार्यक्रमों ने करोड़ों नागरिकों को सम्मानजनक जीवन, स्वास्थ्य सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि तकनीक ने शासन प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया है।

नेपाल भागने की कोशिश नाकाम, टीएमसी नेता जहांगीर खान गिरफ्तार

कोलकाता, 08 जून। पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता जहांगीर खान को नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, वह राज्य से बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोलकाता लाया जा रहा है। दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा क्षेत्र के निवासी जहांगीर हाल ही में हुए फाल्टा विधानसभा उपचुनाव के दौरान चर्चा में आए थे। उन्होंने मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव मैदान से हटने की घोषणा कर दी थी, लेकिन उनका नाम और चुनाव चिह्न ईवीएम पर बना रहा। चुनाव परिणामों में भाजपा ने एक लाख से अधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज की, जबकि जहांगीर चौथे स्थान पर रहे। जहांगीर के खिलाफ 2019 से एक मामला दर्ज है। उन्हें पहले कलकत्ता हाई कोर्ट से गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई से संरक्षण मिला हुआ था, लेकिन 26 मई को अदालत ने यह राहत वापस ले ली। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया।

गोंडवाना एक्सप्रेस में विजिलेंस का छापा, तीन टीटीई के पास मिला 46 हजार रुपये से अधिक अतिरिक्त कैश

जबलपुर, 08 जून (हि.स.)। पश्चिम मध्य रेलवे की विजिलेंस टीम ने सोमवार सुबह जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गोंडवाना एक्सप्रेस में ड्यूटी कर रहे तीन टिकट परीक्षकों को अतिरिक्त नकदी के साथ पकड़ा है। जांच के दौरान तीनों कर्मचारियों के पास घोषित राशि से कुल 46,300 रुपये अधिक पाए गए। विजिलेंस ने प्रकरण दर्ज कर मामले को आगे की कार्रवाई के लिए जबलपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (सीनियर डीसीएम) को सौंप दिया है।

जानकारी के अनुसार ट्रेन क्रमांक 22182 गोंडवाना एक्सप्रेस के स्लीपर और वातानुकूलित कोचों में टीटीई मनोज कुशवाहा, कुंदन कुमार और अनिकेश कुमार की ड्यूटी लगी थी। ट्रेन के जबलपुर पहुंचने से पहले विजिलेंस टीम को एक यात्री द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ टीटीई यात्रियों से कथित रूप से अवैध वसूली कर रहे हैं तथा जुर्माना लेने के बावजूद निर्धारित रसीद जारी नहीं की जा रही है।

सूचना के आधार पर विजिलेंस अधिकारियों ने जबलपुर स्टेशन पर निगरानी शुरू कर दी। सुबह करीब 10 बजे ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही टीम ने तीनों टीटीई को जांच के लिए रोक लिया। इसके बाद उनके पास मौजूद नकदी का मिलान ड्यूटी शुरू करने से पहले किए गए कैश डिक्लेरेशन से किया गया।

जांच में कुंदन कुमार के पास से 32 हजार रुपये, अनिकेश कुमार के पास से 14 हजार रुपये तथा मनोज कुशवाहा के पास से 300 रुपये अतिरिक्त नकद बरामद हुआ।

कुल मिलाकर तीनों कर्मचारियों के पास 46,300 रुपये अधिक पाए गए। विजिलेंस विभाग ने प्रारंभिक जांच पूरी कर प्रकरण को जबलपुर रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉ. मुधर वर्मा को अग्रिम विभागीय कार्रवाई के लिए भेज दिया है। रेलवे प्रशासन मामले की विस्तृत जांच कर रहा है।

भारत का परमाणु जखीरा बढ़ा, पाकिस्तान से रणनीतिक बढ़त मिली

नई दिल्ली, 08 जून। भारत ने अपने परमाणु हथियारों के जखीरे में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्ज की है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु निगरानी संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीपरी) की ताजा वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत के परमाणु वॉरहेड्स की संख्या 180 से बढ़कर 190 हो गई है। इसके साथ ही भारत ने क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान पर रणनीतिक बढ़त हासिल कर ली है, जिसके पास परमाणु हथियारों की संख्या 170 पर स्थिर बनी हुई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया के नौ परमाणु संपन्न देशों के पास कुल मिलाकर लगभग 12,187 परमाणु हथियार मौजूद हैं। इनमें से करीब 9,745 वॉरहेड्स सैन्य भंडारों में संभावित उपयोग के लिए रखे गए हैं, जबकि लगभग 4,012 वॉरहेड्स को मिसाइलों और लड़ाकू विमानों पर तैनात किया जा चुका है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी ने पुलिस व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही पर छेड़ी नई बहस

एक फैसला, कई सवाल और कठघरे में सिस्टम!

विवेक श्रीवास्तव

लखनऊ, 08 जून। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले ने उत्तर प्रदेश की राजनीति, पुलिस व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यसंस्कृति को लेकर नई बहस छेड़ दी है। गाजियाबाद के एक परिवार के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही रद्द करते हुए न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने जो टिप्पणियां कीं, वे अब कानूनी दायरे से निकलकर सार्वजनिक और राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन चुकी हैं।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रदेश में कई अधिकारियों की निष्ठा संविधान के बजाय सत्ताधारी व्यवस्था के प्रति दिखाई देती है। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि ट्रांसफर-पोस्टिंग की व्यवस्था को अधिकारी अच्छी तरह समझते हैं और कई बार उसी के अनुरूप अपने व्यवहार और निर्णय तय करते हैं। अदालत ने

हलचल

- ट्रांसफर-पोस्टिंग से पुलिसिंग तक, उठे कई असहज सवाल
- पुलिस की कार्यशैली पर अदालत की टिप्पणी से सियासी हलचल बढ़ी

यह भी कहा कि चुनिंदा कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट जैसे कठोर कानूनों का इस्तेमाल और कानून के शासन को लेकर समय-समय पर न्यायालयों को हस्तक्षेप करना पड़ा है। दरअसल, पूरा मामला गाजियाबाद के एक परिवार से जुड़ा था, जिसके तीन सदस्यों पर उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक गतिविधियां (निवारण) अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि विवाद मूल रूप से दीवानी प्रकृति का था और उसे संगठित अपराध का स्वरूप देकर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। पर्याप्त आधार नहीं मिलने पर न्यायालय ने पूरी कार्यवाही को निरस्त कर दिया। हालांकि फैसले की सबसे बड़ी चर्चा कानूनी निष्कर्षों से ज्यादा उन टिप्पणियों को लेकर हो रही है, जिनमें अदालत ने प्रदेश की प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। न्यायालय ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारी तंत्र की जवाबदेही किसी राजनीतिक दल या सरकार के प्रति नहीं, बल्कि संविधान और कानून के प्रति होनी चाहिए। यही टिप्पणी अब बहस का केंद्र बन गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत ने जिस मुद्दे को उठाया है, वह नया नहीं है।

पुलिस सुधार, राजनीतिक हस्तक्षेप, अधिकारियों की स्वतंत्रता और ट्रांसफर-पोस्टिंग की संस्कृति पर वर्षों से चर्चा होती रही है।

टीएमसी में टूट की आहट, 14 सांसदों की भाजपा नेताओं से मुलाकात

नई दिल्ली, 08 जून। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) टूटती नजर आ रही है। पहले टीएमसी के कई विधायकों ने अलग गुट बनाया और अब यह टूट संसदीय दल तक पहुंच गई है। टूट की अटकलों के बीच सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के करीब 14 सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव के घर पहुंचे और बंद कमरे में बैठक की।

बैठक में राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले सुखेंदु शेखर भी शामिल हुए। सुखेंदु ने आज ही राज्यसभा और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफे की घोषणा की थी। सूत्रों के अनुसार बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लव देब भी मौजूद रहे। इस राजनीतिक हलचल के बीच तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी इंडी गठबंधन की बैठक के लिए दिल्ली में मौजूद हैं। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस छोड़ने वाले सुखेंदु शेखर ने मीडिया से बातचीत में आरजी कर अस्पताल मामले में तृणमूल कांग्रेस के रवैये की कड़ी आलोचना की।

उन्होंने कहा कि आरजी कर अस्पताल मामले पर सार्वजनिक रूप से उन्होंने राय रखी थी। तब से पार्टी के भीतर उन्हें नजरअंदाज किया जाने लगा।

सुखेंदु ने कहा कि उन्होंने कुछ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आंतरिक जांच की मांग की थी क्योंकि मेरा मानना था कि सबूतों को नष्ट करने में उनकी अहम भूमिका थी। इसके कारण उन्हें पार्टी से अलग थलग कर दिया गया था।

गर्भावस्था में नियमित जांच व समय पर पहचान से सुरक्षित होता है मातृत्व : शुक्ल

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूर्ण होने पर आज प्रदेश में विशेष मातृत्व स्वास्थ्य शिविर होंगे आयोजित

भोपाल। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने सोमवार को कहा कि सुरक्षित मातृत्व प्रत्येक महिला का अधिकार है। गर्भावस्था दी समय पर जांच एवं उच्च जोखिम स्थितियों की शीघ्र पहचान से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है और सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित किया जा सकता है। राज्य सरकार गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने प्रदेश की सभी गर्भवती महिलाओं एवं उनके परिजनों से अपील की है कि वे 9 जून को आयोजित विशेष प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शिविरों में पहुंचकर निःशुल्क जांच, परामर्श एवं उपचार सुविधाओं का लाभ अवश्य लें। उन्होंने कहा कि इस अभियान को जन-आंदोलन के रूप में संचालित करते हुए प्रत्येक गर्भवती महिला तक गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाए, जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में और कमी लाई जा सके। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) के अंतर्गत मध्य प्रदेश में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अभियान के तहत पंजीकृत 14.31 लाख गर्भवती महिलाओं में से 10.25 लाख महिलाओं की प्रसवपूर्व जांच (एएनसी) की गई, जो कुल पंजीकृत गर्भवतियों का लगभग 72 प्रतिशत है। जांच के दौरान 2.94 लाख महिलाओं को उच्च जोखिम गर्भावस्था (हाई रिस्क प्रेगनेंसी-एचआरपी) के रूप में चिन्हित किया गया, जिनमें से 2.60 लाख अर्थात 88 प्रतिशत महिलाओं को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार आवश्यक उपचार, प्रबंधन एवं रेफरल सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अपर मिशन संचालक दिशा प्रणय नागवंशी ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के सफलतापूर्वक 10 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 9 जून को प्रदेश के सभी जिलों में विशेष पीएमएसएमए शिविर आयोजित किए जाएंगे। राज्य के सभी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों, जिला चिकित्सालयों, सिविल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण मातृ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। विशेष शिविरों में गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्व एवं प्रसवोत्तर जांच, नवीन एवं छूटी हुई गर्भवतियों का पंजीयन, उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं की पहचान, उपचार एवं नियमित फॉलोअप सुनिश्चित किया जाएगा। महिलाओं की रक्तचाप, वजन, बीएमआई, मेडिकल एवं प्रसूति इतिहास की जांच के साथ ही आवश्यक प्रयोगशाला परीक्षण भी किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत हीमोग्लोबिन, यूरिन एल्बुमिन एवं शुगर, एचआईवी, हेपेटाइटिस-बी, सिफलिस, मलेरिया, सिकल सेल स्क्रीनिंग, ब्लड ग्रुपिंग और ओजीटीटी जैसी महत्वपूर्ण जांचें उपलब्ध कराई जाएंगी। आवश्यकता अनुसार सोनोग्राफी एवं विशेषज्ञ परामर्श की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में आयरन-फोलिक एसिड, कैल्शियम सहित आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं तक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों तथा सुमन हेल्प डेस्क की सक्रिय भागीदारी रहेगी। जरूरतमंद महिलाओं के लिए 108 एम्बुलेंस के माध्यम से निःशुल्क परिवहन सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेशभर में व्यापक जन-जागरूकता अभियान भी संचालित किया जाएगा। ग्राम स्तर पर प्रचार-प्रसार, सोशल मीडिया अभियान, वीएचएसएनडी, जन आरोग्य समितियों, स्व-सहायता समूहों एवं पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सुरक्षित मातृत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाएगी।

तेज रफ्तार हाईवा ने स्कूटी सवार को रौंदा, मौत

जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के माढ़ोताल थाना क्षेत्र में रविवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। खजरी खिरिया बाईपास पर तेज रफ्तार हाईवा ने स्कूटी को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

पुलिस के अनुसार, घटना रात करीब दो बजे की है। बताया जा रहा है कि तेज गति से आ रहा हाईवा अनियंत्रित होकर आगे चल रही स्कूटी से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी हाईवा के नीचे फंस गई और करीब 50 मीटर तक सड़क पर घिसटती चली गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सड़क पर घर्षण के कारण चिंगारियां निकलने लगीं और कुछ ही देर में स्कूटी के साथ हाईवा के निचले हिस्से में आग भड़क उठी। इसी दौरान बाईपास से गुजर रहे अन्य ट्रक चालकों ने तत्परता दिखाते हुए युवक को वाहन के नीचे से बाहर निकाला। सूचना मिलते ही माढ़ोताल थाना प्रभारी अपूर्वा चौरसिया और हनुमानताल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान और हादसे के अन्य पहलुओं की जांच पुलिस कर रही है।

हादसे के बाद हाईवा चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त हाईवा को जब्त कर आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फरार चालक की तलाश के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। सोमवार को पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

रामजानकी ट्रस्ट की 107 बीघा भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई

ग्वालियर। सोमवार को प्रभारी कलेक्टर कुमार सत्यम के निर्देश पर गई जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने विकासखंड घाटीगांव के अंतर्गत झांकरी ग्राम में बड़ी कार्रवाई कर श्री रामजानकी ट्रस्ट रानी घाटी मंदिर की 107 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया।

एसडीएम भितरवार राजीव समाधिया के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के दौरान भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए लोगों को बेदखल कर मंदिर की जमीन का विधिवत कब्जा मंदिर के पुजारी कमलानंद महाराज को सौंपा गया। अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि की अनुमानित बाजार कीमत 11 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है।

कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग एवं पुलिस बल की मौजूदगी में मौके पर कब्जा दिलाने की प्रक्रिया पूरी की गई। मंदिर के पुजारी द्वारा भूमि की सीमाओं पर मुड्डियां गड़वाकर भूमि का कब्जा प्राप्त किया गया। जानकारी के अनुसार लगभग 35 अतिक्रमणकारी पिछले 25 से 30 वर्षों से इस भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए थे। यह कार्रवाई एसडीएम भितरवार राजीव समाधिया, एसडीओपी जितेन्द्र नगाइच, तहसीलदार रुचि अग्रवाल, नायब तहसीलदार पूजा मावई, थाना प्रभारी भितरवार एवं चीनोर सहित राजस्व विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा पुलिस बल की उपस्थिति में हुई।

मां-बेटे समेत पड़ोसी पर हमला

जबलपुर। गढ़ा थाना अंतर्गत कोष्टा मोहल्ला में बदमाशों ने मां-बेटे समेत पड़ोसी पर हमला कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है । पुलिस के मुताबिक नीरज यादव 31 वर्ष निवासी कोष्टा मोहल्ला गढ़ा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह नैक्शा वर्कशॉप में काम करता है बीती रात लगभग 10 अपने घर में मोबाइल में गेम खेल रहा था। मोहल्ले में झगड़े की आवाज आने पर बाहर आकर देखा हितकारिणी स्कूल के पास रहने वाला बंटी एवं चौधरी मोहल्ला निवासी बम्बू, अम्बर व अन्य साथी उसके पड़ोसी साहिल सेन से शराब पीने के लिये एक हजार रुपए मांग रहे थे, साहिल ने पैसे देने से मना किया तो सभी साहिल के साथ विवाद करते हुये हाथ मुक्कों से मारपीट करने लगे, साहिल की मॉ कल्पना सेन घर से बाहर आकर बीच बचाव करने लगीं तो उनके साथ भी मारपीट की वह बीच बचाव करने लगा तो उसके साथ बंटी, बम्बू, अम्बर एवं उनके साथी मारपीट करने लगे बंटी ने धारदार हथियार से हमला कर वायें हाथ की हथेली में चोट पहुॅचा दी।

मंत्री प्रहलाद पटेल ने की विभागीय योजनाओं की समीक्षा, पारदर्शी क्रियान्वयन पर दिया जोर

भोपाल। मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सोमवार को विकास भवन में विभागीय योजनाओं के कार्यों, वित्तीय प्रावधान और व्यय की योजनावार समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शासन की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाए, जिससे समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ सुगमता से पहुँचे सके।

मंत्री पटेल ने निर्देशित किया कि जिन योजनाओं में इस तिमाही में व्यय कम हुआ है, वहां कार्यों की गति को तत्काल बढ़ाया जाए और भारत सरकार से संबंधित मुद्दों पर निरंतर फॉलो-अप कर शीघ्र कार्रवाई की जाए। उन्होंने 'जन मन' योजना की किश्त का समय पर भुगतान करने, सोशल ऑडिट के लिए विशेष सॉफ्टवेयर का निर्माण करने तथा 'बीबी रामजी योजना' के लिए वास्तविकता के आधार पर बजट तैयार करने के निर्देश दिए।

मंत्री पेटल ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, रसोइयों को मानदेय, मुख्यमंत्री आवास मिशन, रेडी टू टेक होम राशन, मजरा टोला और क्षतिग्रस्त पुलों के निर्माण संबंधी योजनाओं की भी समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों को विभागीय संरचना के पुनर्गठन और योजनाओं के क्रियान्वयन को गति देने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में विभाग के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए विकास आयुक्त कार्यालय एवं पंचायत राज संचालनालय के विलय के प्रस्ताव पर एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। मंत्री पटेल ने विलय के उपरांत संचालनालय, संभागीय, जिला एवं जनपद कार्यालयों के लिए प्रस्तावित स्वीकृत पदों की गहन समीक्षा की। इस अवसर पर संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

डायल-112 के जवानों ने घायलों को वरित सहायता पहुंचाकर अस्पताल में कराया भर्ती

भोपाल। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के थाना जावद क्षेत्र में डायल-112 जवानों की तत्परता एवं संवेदनशील कार्यवाही से सड़क दुर्घटना में घायल हुई दो महिलाओं एवं एक पुरुष को समय पर अस्पताल पहुँचाकर उपचार उपलब्ध कराया गया। त्वरित सहायता मिलने से घायलों को समय रहते चिकित्सकीय सुविधा मिल सकी।

पुलिस मुख्यालय द्वारा जानकारी दी गई कि सोमवार को राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम डायल-112 भोपाल में सूचना प्राप्त हुई कि थाना जावद क्षेत्र अंतर्गत नानपुरिया रोड पर दो कारों की आमने-सामने टक्कर हो गई है, जिसमें दो महिलाएँ एवं एक पुरुष घायल हो गए हैं। पुलिस सहायता की आवश्यकता है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाना जावद क्षेत्र में तैनात डायल-112 वाहन को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। डायल-112 स्टाफ आरक्षक 216 सुरेश धनगर एवं पायलट अरुण चंदेल ने मौके पर पहुंचकर पाया कि दो कारों की भिड़ंत में तीन व्यक्ति घायल हो गए थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डायल-112 जवानों ने त्वरित कार्यवाही करते हुए सभी घायलों को सुरक्षित डायल-112 वाहन की सहायता से शासकीय चिकित्सालय, जावद पहुँचाया।डायल-112 की त्वरित प्रतिक्रिया से घायलों को समय पर चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध हो सकी।

हजारों लोगों ने लिया नि :शुल्क स्वास्थ्य व रक्तदान शिविर का लाभ, 1200 मरीजों का परीक्षण

ग्वालियर। निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं रक्तदान शिविर का आयोजन करौली माता मंदिर, महलगांव पर किया गया। शिविर में क्षेत्र सहित आसपास के हजारों लोगों ने पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त किया। शिविर के दौरान लगभग 1200 मरीजों का स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण किया गया। विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों की जांच कर आवश्यक परामर्श दिया गया तथा जरूरतमंदों को निःशुल्क दवाइयों एवं चश्मों का वितरण भी किया गया। वहीं समाजहित में बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्साहपूर्वक रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से महापौर शोभा सिकरवार, जड़ेरुआ सरकार महाराज एवं जयारोग्य अस्पताल के अधीक्षक डॉ. सुधीर सक्सेना उपस्थित रहे। अतिथियों ने शिविर के आयोजन की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायी पहल बताया। इस अवसर पर समाजसेवी अनंत शर्मा ने कहा कि शिविर का उद्देश्य समाज के जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि ह्लसेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और हम जीवन पर्यंत इसी सेवा पथ पर चलते रहेंगे।ह्लशिविर के सफल आयोजन में क्षेत्र के युवाओं, सामाजिक कार्यकताओं एवं सहयोगी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उपस्थित लोगों ने आयोजन की सराहना करते हुए ऐसे जनहितकारी कार्यक्रमों को निरंतर आयोजित किए जाने की अपेक्षा व्यक्त की।

बक्सर राजपूत क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष बायलाज का कर रहे उल्लंघन: सिंह

रायपुर। बक्सर राजपूत क्षत्रिय समाज के प्रदेशध्यक्ष संतोष सिंह ने प्रेस क्लब रायपुर पहुंचकर पत्रकारवार्ता लेते हुए बताया कि समाज के अध्यक्ष द्वारा बायलाज का उल्लंघन किया जा रहा है। पहले सदस्यता शुल्क 10 रुपये था जिसे बिना सदस्यों की सहमति से 50 रुपये किया गया है जिसका समाज विरोध कर रहा है। उन्होंने बताया कि विरोध करने वाले लोगों को सामाजिक कार्य जैसे दशगात्र, मांगलिक कार्य आदि में शामिल नहीं होने के लिए कहा जा रहा है। बिलासपुर के एक सदस्य को दंड स्वरूप राशि सहयोग राशि के नाम से 11 लाख रुपये समाज में सम्मिलित करने के लिए कहा गया जिसे उन्होंने ठुकराया। अब वे समाज से बाहर है। अध्यक्ष के मनमाने निर्णय से सामाजिक कार्य भी प्रभावित हो रहे है। महिलाओं को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। सवाल पूछने पर लोगों को समाज से निकाल रहे है। चार पांच लोग मिलकर तानाशाही चला रहे है। उन्होंने कहा कि सामाजिक कार्यों से रोकने वाले अध्यक्ष द्वारा बायलाज के नियमों का पालन नहीं किया गया तो जुलाई में आयोजित बैठक में बहिष्कार की घोषणा कर उनके खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा।

इंस्टाग्राम आईडी को लेकर दोस्त बना कातिल, गला घोंटकर की हत्या

इंदौर। बाणगंगा थाना क्षेत्र में दोस्ती को शर्मसार करने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक युवक ने अपने ही दोस्त की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन घटनास्थल पर मिली एक चप्पल ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया।

पुलिस के अनुसार मृतक रोहित और आरोपी देवेंद्र पीओपी लगाने का काम करते थे। दोनों कई वर्षों से साथ रह रहे थे और एक ही मोबाइल फोन का उपयोग करते थे। इतना ही नहीं, दोनों एक ही इंस्टाग्राम आईडी भी संचालित करते थे। घटना वाले दिन दोनों एक निमार्णाधीन भवन में बैठकर शराब पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान इंस्टाग्राम आईडी चलाने को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि देवेंद्र ने गुस्से में आकर रोहित का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। शुरूआत में देवेंद्र ने पुलिस को बताया कि वह पार्टी के बाद घर लौट आया था और उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। वहीं सुबह जब रोहित नहीं उठा तो परिजनों को इसकी सूचना दी गई। परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद जांच शुरू की गई। एडिशनल डीसीपी प्रियंका डुडवे ने बताया कि जांच के दौरान घटनास्थल से एक चप्पल बरामद हुई। इसी अहम सुराग के आधार पर पुलिस ने आरोपी तक पहुंच बनाई। पूछताछ में पहले तो देवेंद्र पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने हत्या करना स्वीकार कर लिया।

आरक्षकों ने सीपीआर देकर बचाई जान, डीजीपी ने की पुरस्कृत करने की घोषणा

भोपाल। मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों को नियमित रूप से प्रदान किए जाने वाले सीपीआर (कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन) प्रशिक्षण का सकारात्मक परिणाम लगातार सामने आ रहे हैं। इसी के परिणामस्वरूप सोमवार को पुलिस आयुक्त कार्यालय, भोपाल में पदस्थ दो आरक्षकों ने त्वरित सूझबूझ, तत्परता एवं सीपीआर कौशल से एक अचेत नागरिक को समय रहते जीवनरक्षक सहायता प्रदान कर उसकी जान बचाई। इस सराहनीय कार्य के लिए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कैलाश मकवाणा ने दोनों पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की है।

पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, कार्यालय पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस भोपाल में एक आगंतुक अचानक अस्वस्थ होकर अचेत अवस्था में जमीन पर गिर पड़ा। घटना को देखते हुए वहां मौजूद चालक आरक्षक क्रमांक 858 मुकेश साहू एवं गनमैन आरक्षक क्रमांक 3685 रंजीत रघुवंशी ने तत्काल स्थिति की गंभीरता को समझते हुए बिना समय गंवाए प्राथमिक उपचार प्रारंभ किया।

दोनों आरक्षकों ने प्रशिक्षित दक्षता का परिचय देते हुए अचेत व्यक्ति को तत्काल सीपीआर (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन) देना शुरू किया। उन्होंने बारी-बारी से लगातार सीपीआर प्रदान किया, जिसके परिणामस्वरूप कुछ ही समय में आगंतुक को होश आ गया। प्राथमिक उपचार के उपरांत उसे बेहतर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य लाभ के लिए अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा समय-समय पर पुलिसकर्मियों को सीपीआर एवं अन्य आपातकालीन जीवनरक्षक तकनीकों का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, ताकि दुर्घटना, हृदयाघात अथवा अन्य आपात स्थितियों में नागरिकों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

संजय गांधी थर्मल पॉवर स्टेशन की यूनिट-3 ने लगातार 100 दिन बिजली उत्पादन कर रचा इतिहास

भोपाल। मध्य प्रदेश को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में मप्र पावर जनरेटिंग कंपनी के संजय गांधी थर्मल पॉवर स्टेशन बिरसिंगपुर (एसजीपीटीपीएस) ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। स्टेशन की यूनिट नंबर 3 ने बीते 27 फरवरी से बिना रुके लगातार 100 दिनों तक बिजली पैदा करने का स्वर्णिम आंकड़ा छू लिया है।

गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भी कंपनी की कुल 13 उत्पादन इकाइयों ने 100 से अधिक दिनों तक लगातार निर्बाध बिजली उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया था। इस शानदार ट्रैक रिकॉर्ड में अकेले संजय गांधी ताप विद्युत गृह बिरसिंगपुर का दबदबा रहा; जहां इसी यूनिट-3 ने पहले भी एक बार यह मुकाम हासिल किया था, वहीं स्टेशन की यूनिट-4 दो बार और यूनिट-5 ने एक बार इस ऐतिहासिक उपलब्धि को अपने नाम दर्ज कराया था।

सटीक परिचालन से गढ़े गए दक्षता के नए मानदंड- मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी के प्रबंध संचालक मनजीत सिंह ने सोमवार को जानकारी देते हुए इस रिकॉर्ड परिचालन अवधि के दौरान यूनिट ने 89.18 प्रतिशत का प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर बनाए रखा, जो बिजली उत्पादन के लिए इस इकाई की उच्च उपलब्धता और तकनीकी मजबूती को प्रमाणित करता है। इसके साथ ही, इकाई ने 80.07 प्रतिशत का प्लांट लोड फैक्टर दर्ज कर अपनी वास्तविक उत्पादन क्षमता के कुशल उपयोग का लोहा मनवाया। ऊर्जा दक्षता के मोर्चे पर भी प्रबंधन का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा, जहां आंतरिक सहायक विद्युत खपत को महज 9.17 प्रतिशत पर सीमित रखकर बिजली की बड़ी बचत की गई।

उत्पादन इकाइयाँ उच्चतम विश्वसनीयता के साथ काम करने में सक्षम- प्रबंध संचालक मनजीत सिंह ने इस गौरवमयी उपलब्धि पर गहरी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पूरी टीम की सराहना की। उन्होंने कहा, ऱहमारे इंजीनियरों और तकनीकी टीम ने उत्कृष्ट संधारण और कुशल संचालन के दम पर बार-बार यह साबित किया है कि कंपनी की बिजली उत्पादन इकाइयाँ उच्चतम विश्वसनीयता के साथ काम करने में पूरी तरह सक्षम हैं। यही वजह है कि हमारी इकाइयाँ लगातार राष्ट्रीय स्तर के कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं और उत्कृष्ट प्रदर्शन का एक बेहद मजबूत रिकॉर्ड बना रही हैं।ऱ उन्होंने कहा यह उपलब्धि तकनीकी कार्मिकों एवं ठेका श्रमिकों की सतत निगरानी, समर्पण तथा समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण संधारण का परिणाम है।

डायरेक्टर टेक्निकल सुबोध निगम ने कहा कि यह सफलता पूरी टीम के आपसी तालमेल, सक्रिय कार्यप्रणाली और संकट के समय त्वरित फैसलों का नतीजा है। उन्होंने विश्वास जताया कि हमारे सभी विद्युत गृह भविष्य में भी प्रदेश को निर्बाध और भरोसेमंद बिजली देने में हमेशा आगे रहेंगे।

मप्र पुलिस की संपत्ति संबंधी अपराधों पर बड़ी कार्रवाई, 4 दिनों में 3 करोड़ से अधिक मूल्य की चोरी एवं ठगी गई सामग्री बरामद

भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेश में संपत्ति संबंधी अपराधों की के त्वरित निराकरण के लिए लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में विगत चार दिनों के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों में संचालित विशेष अभियानों, तकनीकी विश्लेषण एवं सघन विवेचना के माध्यम से पुलिस ने 3 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की चोरी एवं ठगी गई संपत्ति बरामद करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस मुख्यालय द्वारा सोमवार को जानकारी दी गई ग्वालियर जिले में कोतवाली पुलिस ने हॉलमार्क कराने के नाम पर ग्राहकों का सोना लेकर फरार हुए ज्वेलर्स संचालक एवं उसके साथी को मेरठ से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपये मूल्य के 931 ग्राम सोने के जेवरात बरामद किए। वहीं डबरा सिटी पुलिस ने मात्र 24 घंटे में एक फर्जी लूटकांड का खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर 49 लाख 50हजार रुपये मूल्य के जेवरात, नगदी एवं मोटरसाइकिल बरामद की। इसी प्रकार महाराजपुरा पुलिस ने वर्ष 2023 में हुई चोरी की घटना का खुलासा कर लगभग 8 लाख रुपये मूल्य की लायसेंसी रिवॉल्वर, जेवरात एवं अन्य सामग्री बरामद की।पुलिस ने बताया कि मुरैना जिले में देवगढ़ थाना पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पदार्फाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया तथा उनके कब्जे से लगभग 55 लाख रुपये से अधिक मूल्य की चोरी गई संपत्ति, राइफल, कारतूस, नगदी, जेवरात एवं घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद किए।

आरोपियों पर 32हजार 500 रुपये का इनाम घोषित था।जबलपुर जिले के गोहलपुर थाना पुलिस ने नकबजनी की घटना का खुलासा कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लगभग 15 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवरात एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की। देवास पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्रम के तहत सूने मकानों में चोरी करने वाले एक संगठित गिरोह का पदार्फाश किया। पुलिस ने दो महिलाओं सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लगभग 12 लाख 50 हजार रुपये की सम्पूर्ण चोरी गई संपत्ति, वाहन एवं मोबाइल फोन बरामद किए।भोपाल के टीटी नगर थाना पुलिस ने नकबजनी के एक मामले में कार्रवाई करते हुए लगभग 7 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए, जिनमें हार, चूड़ियां, अंगूठी, मंगलसूत्र एवं पाजेब शामिल हैं। इंदौर में भंवरकुआ थाना पुलिस ने खंडवा नाका स्थित एक पान दुकान में हुई चोरी की घटना का 24 घंटे के भीतर खुलासा कर एक आरोपी एवं एक विधि विरुद्ध बालक को अभिरक्षा में लिया। लगभग 250 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का विश्लेषण कर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की तथा लगभग 4 लाख रुपये मूल्य की चोरी गई संपत्ति बरामद की है।

पार्वती नदी में अवैध रेत उत्खनन पर पुलिस का शिकंजा,चार ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

राजगढ़। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के सुठालिया थाना पुलिस ने रविवार की रात ग्राम महाराजखेड़ा में पार्वती नदी के किनारे से दबिश देकर रेत चोरी कर ले जा रहे चार ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त किए हैं।थानाप्रभारी अनिल राहोरिया ने सोमवार को बताया कि पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर बीती रात ग्राम महाराजखेड़ा स्थित पार्वती नदी किनारे दबिश दी, जहां से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा था, पुलिस को देखकर ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। जांच में पाया गया कि बिना रॉयल्टी के नदी से रेत निकालकर उसका परिवहन किया जा रहा था। पुलिस ने मौके से दो सोनालिका और दो स्वराज कंपनी के ट्रैक्टर मय रेत भरी ट्रॉली जब्त किए।

मध्य प्रदेश 7.63 लाख से अधिक बालिकाओं का एचपीवी टीकाकरण कर देश के शीर्ष राज्यों में हुआ शामिल

भोपाल। महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए देशव्यापी एचपीवी(ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण अभियान में मध्य प्रदेश शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया है। स्वास्थ्य अमले, सहयोगी विभागों की प्रतिबद्धता एवं सतत मॉनिटरिंग के परिणामस्वरूप प्रदेश में 7.63 लाख से अधिक पात्र बालिकाओं का सफलतापूर्वक एचपीवी टीकाकरण किया जा चुका है।

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ने एचपीवी टीकाकरण अभियान में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर यह सिद्ध कर दिया है कि जनभागीदारी, स्वास्थ्य अमले की प्रतिबद्धता और प्रभावी नेतृत्व के बल पर बड़े से बड़े जनस्वास्थ्य अभियानों को समय से पहले सफल बनाया जा सकता है। उन्होंने अभियान से जुड़े चिकित्सकों, नर्सिंग स्टॉफ, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, एएनएम, शिक्षकों, जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें सफलता के लिये बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह अभियान प्रदेश की बेटियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाकर सुरक्षित भविष्य देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 28 फरवरी 2026 को महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से देशव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया था। यह अभियान मूल रूप से 90 दिनों के लिए निर्धारित था, लेकिन मध्य प्रदेश ने निर्धारित लक्ष्य को मात्र 60 दिनों में ही पूर्ण कर लिया, जो प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की दक्षता और प्रभावी क्रियान्वयन का उत्कृष्ट उदाहरण है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर भारत में महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे सामान्य कैंसर है तथा इसके अधिकांश मामलों का प्रमुख कारण एचपीवी संक्रमण होता है। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार यह ऐसा कैंसर है, जिसे प्रभावी टीकाकरण के माध्यम से काफी हद तक रोका जा सकता है। एचपीवी वैक्सीन बालिकाओं को भविष्य में इस गंभीर बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने का सुरक्षित, प्रभावी एवं वैज्ञानिक उपाय है।

अभियान की सफलता में स्वास्थ्य विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सक्रिय सहभागिता रही। प्रदेश के सभी जिलों में व्यापक जनजागरूकता, सूक्ष्म कार्ययोजना (माइक्रो प्लानिंग) एवं सतत मॉनिटरिंग के माध्यम से यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है।

किराया बढ़ाने की मांग को लेकर ऑटो चालकों का अनोखा प्रदर्शन

फटे कपड़े दिखाकर जताई नाराजगी

भोपाल। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की लगातार बढ़ती कीमतों से परेशान ऑटो चालकों ने सोमवार को राजधानी भोपाल में अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। रायसेन रोड स्थित छावनी पठार क्षेत्र में बड़ी संख्या में ऑटो चालक एकत्र हुए और हाथों में फटे अंडरवियर लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि बढ़ती महंगाई और ईंधन की कीमतों ने उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर कर दी है कि रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो गया है। रायसेन रोड स्थित शनि मंदिर के पास आयोजित इस प्रदर्शन में ऑटो चालकों ने किराया बढ़ाने की मांग उठाई।

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वर्षों से ऑटो किराए में कोई संशोधन नहीं हुआ है, जबकि ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसका सीधा असर उनकी आय और परिवार के भरण-पोषण पर पड़ रहा है। ऑटो संगठन के अध्यक्ष संजू अहिरवार ने बताया कि सीएनजी ऑटो में प्रतिदिन करीब 500 रुपये की गैस भरवानी पड़ती है। इसके बाद पूरे दिन की मेहनत से लगभग 1200 रुपये की कमाई होती है। इसमें से ईंधन खर्च निकालने के बाद जो राशि बचती है, उसी से वाहन की किश्त, रखरखाव और परिवार का खर्च चलाना पड़ता है। ऐसे में प्रतिदिन की वास्तविक बचत बेहद कम रह जाती है।प्रदर्शन के दौरान चालकों ने फटे अंडरवियर दिखाकर अपनी बदहाल आर्थिक स्थिति का प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि बढ़ती महंगाई, वाहन की किश्तें, ईंधन खर्च और घरेलू जिम्मेदारियों के बीच उनकी आमदनी लगातार घटती जा रही है। कई चालकों ने कहा कि दिनभर मेहनत के बावजूद परिवार की बुनियादी जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो रहा है। ऑटो चालकों का कहना है कि सरकार को मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए ऑटो किराए का पुनर्निर्धारण करना चाहिए। उनका तर्क है कि किराया बढ़ने से ही वे वाहन की किश्त समय पर चुका पाएंगे और अपने परिवार का सम्मानजनक तरीके से पालन-पोषण कर सकेंगे।

मप्र से कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन ने भरा नामांकन, तीसरी राज्यसभा सीट पर घमासान

भोपाल। मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने सोमवार को विधानसभा स्थित रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपने वरिष्ठ नेताओं और अधिकांश विधायकों की मौजूदगी दर्ज कराई। नामांकन प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता और विधायक मौजूद रहे।

विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मीनाक्षी नटराजन ने अपना नामांकन प्रस्तुत किया। इस दौरान जीतू पटवारी स्वयं विधायकों को रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष तक लेकर पहुंचे। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि यह केवल एक चुनाव नहीं, बल्कि विचारधाराओं की लड़ाई है। उन्होंने कहा, कांग्रेस किसानों, मजदूरों, आदिवासियों और आम लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष करती रही है। हम सभी एकजुट होकर यह चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। नटराजन ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि खुद को 'पार्टी विद डिफरेंस बताने वाली भाजपा की राजनीतिक शुचिता और नैतिकता इस चुनाव में स्पष्ट दिखाई दे रही है।भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा महेश केवट को सोमवार को तीसरे उम्मीदवार के रूप में उतारने के ऐलान के बाद कांग्रेस ने भी अपनी राजनीतिक रणनीति तेज कर दी है। पार्टी सूत्रों के अनुसार विधायकों से लगातार संपर्क बनाए रखा जा रहा है और उन्हें भोपाल में रहने के निर्देश दिए गए हैं।

जरूरत पड़ने पर विधायकों को दूसरे राज्य में शिफ्ट करने की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद, राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी के साथ दिल्ली रवाना हुए हैं। राजनीतिक हलकों में इसे राज्यसभा चुनाव से जुड़ी रणनीतिक तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है, हालांकि मसूद ने इसे निजी दौरा बताया है। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक डॉ. विक्रांत भूरिया ने भाजपा पर कांग्रेस विधायकों को प्रलोभन देने का आरोप लगाया है। भूरिया ने कहा कि कांग्रेस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और अपने विधायकों की एकजुटता सुनिश्चित करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगी।नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि भाजपा का कैंडिडेट डमी कैंडिडेट है।

वहीं कांग्रेस विधायकों की शिफ्टिंग पर सिंघार ने कहा कि हम लोग चर्चा करेंगे। फिर तय करेंगे कि बाहर जाना है या नहीं जाना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा के दावों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस के सभी विधायक पूरी तरह एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा गलतफहमी में है और पार्टी के सभी विधायक मजबूती से कांग्रेस उम्मीदवार के साथ खड़े हैं। वहीं कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे और सुनील उईके ने भी दावा किया कि मीनाक्षी नटराजन को अपेक्षा से अधिक समर्थन मिलेगा और चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहेगा।

राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका वरिष्ठ नेता नरेश ज्ञानचंदानी ने छोड़ी पार्टी

भोपाल। राज्यसभा चुनाव के बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। भोपाल की हुजूर विधानसभा सीट से दो बार कांग्रेस प्रत्याशी रहे वरिष्ठ नेता नरेश ज्ञानचंदानी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वहीं बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे के मुख्यमंत्री निवास पहुंचने से राजनीतिक हलकों में नई चचाओं ने जोर पकड़ लिया है। इन घटनाक्रमों ने राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की रणनीति और संगठनात्मक एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नरेश ज्ञानचंदानी ने सोमवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को भेजे अपने इस्तीफा पत्र में 37 वर्षों की राजनीतिक यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा पार्टी हित को सर्वोपरि रखा और कभी किसी पद या टिकट की मांग नहीं की। उन्होंने लिखा कि केवल राहुल गांधी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए किए गए एक ट्वीट को लेकर जिस तरह की प्रतिक्रिया मिली, उससे वे आहत हैं और इसी कारण पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया है। ज्ञानचंदानी का इस्तीफा ऐसे समय आया है जब राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक मुकाबला चरम पर है। दरअसल, कांग्रेस द्वारा मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद ज्ञानचंदानी ने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से अपनी असहमति जताई थी। उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को टैग करते हुए लिखा था कि 2028 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए ऐसे नेता को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए जिसकी प्रदेश में मजबूत राजनीतिक पकड़ हो और जो संगठन को चुनावी बढ़त दिला सके। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को सबसे उपयुक्त विकल्प बताया था। इस पोस्ट के बाद पार्टी में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चर्चा भी शुरू हो गई थी। अपने इस्तीफा पत्र में ज्ञानचंदानी ने कहा कि वर्ष 1989 में तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय मोतीलाल वोरा उन्हें राजनीति में लेकर आए थे। बाद में उन्हें दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे वरिष्ठ नेताओं के साथ काम करने का अवसर मिला। उन्होंने दावा किया कि 2018 के विधानसभा चुनाव में उनके उम्मीदवार बनने से सिंधी समाज का बड़ा वर्ग कांग्रेस के साथ जुड़ा, जिसका लाभ पार्टी को कई सीटों पर मिला।

मप्र के इंदौर में आज से शुरू होगी ब्रिक्स देशों की बैठक, 20 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल

भोपाल। मध्य प्रदेश के इंदौर में मंगलवार, 09 जून से ब्रिक्स देशों के एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप एवं कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो रही है। आगामी 13 जून तक चलने वाली इस बैठक में 20 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारत इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है।केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए आयोजन को लेकर विस्तृत रुपरेखा साझा की। उन्होंने बताया कि तय कार्यक्रम के मुताबिक 9 से 11 जून तक कृषि कार्य समूह की बैठकें होंगी और इसके बाद 12 से 13 जून को मुख्य कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान खाद्य हानि को कम करने, पशुपालन, मत्स्य पालन और किसानों के अधिकारों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी गंभीर मंथन होगा।केन्द्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि ब्रिक्स की शुरूआत 2006 में हुई थी और आज 11 सदस्य देशों व 10 साझेदार देशों के साथ यह विश्व के सबसे प्रभावशाली समूहों में से एक बन गया है। भारत की अध्यक्षता में अब तक ब्रिक्स कृषि कार्य समूह की लगभग आठ बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में खाद्य सुरक्षा, मत्स्य पालन, पशुपालन सहित कृषि से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई है।उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए यह अत्यंत गौरव और प्रसन्नता का विषय है कि इंदौर में ब्रिक्स देशों के एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप एवं कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हो रही है। इस बार यह सम्मेलन इसलिए भी खास है, क्योंकि पहली बार ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की यह बैठक मंत्री स्तर पर आयोजित की जा रही है, जिसमें सदस्य और साझेदार देशों सहित लगभग 20 देशों के प्रतिनिधि शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक दृष्टिकोण से यह समूह बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया की लगभग 42% कृषि भूमि, 68 % कृषि जोतें और करीब 42 % खाद्य उत्पादन इन्हीं ब्रिक्स देशों के पास है।

इस मंच पर होने वाला सहयोग पूरी दुनिया की खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है। भारत इससे पहले भी साल 2012, 2016 और 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर चुका है, जिसके दौरान 2016 में 'ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच' जैसी बड़ी पहल शुरू की गई थी।केन्द्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष के आयोजन में छोटे और सीमांत किसान हमारी हर नीति और सहयोग के केंद्र में रहेंगे। कृषि विकास का वास्तविक अर्थ तभी सिद्ध होगा जब किसानों की आय बढ़ेगी और उनकी आजीविका सुरक्षित होगी। इस बार मुख्य रूप से चार विषयों- खाद्य सुरक्षा, पोषण एवं आजीविका; कृषि व्यापार एवं सहयोग; जलवायु अनुकूलन एवं सतत कृषि; तथा कृषि एवं खाद्य प्रणालियों में नवाचार व साझेदारी को सशक्त बनाने पर विशेष काम किया जा रहा है।उन्होंने जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौती पर बात करते हुए कहा कि पुनयोर्जी कृषि, सतत पद्धतियों और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी आधुनिक तकनीकों को छोटे किसानों तक पहुँचाने के साथ ही कृषि के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए महिलाओं और युवाओं के नेतृत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में 12 जून को ह्ललघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षाह्व विषय पर एक विशेष मंत्री स्तरीय संवाद भी होगा।

गाड़गंगा नदी में मिला युवक का शव

राजगढ़। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर क्षेत्र में सोमवार को गाड़गंगा नदी में एक युवक का शव मिला है। घटना छोटे पुल के समीप तीसरे नाले के पास की है, जहां हाट बाजार के चलते बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। लोगों की नजर नदी में पड़े शव पर पड़ी, जिसके केवल सिर के बाल पानी के ऊपर दिखाई दे रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित किया। स्थानीय युवक मुकेश मोंगिया की मदद से शव को नदी से बाहर निकाला गया। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस जांच में मृतक की पहचान 25 वर्षीय अर्जुन सोनी निवासी खिलचीपुर के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि अर्जुन वर्तमान में अपनी मां के साथ जीरापुर में रह रहा था। युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। गाड़गंगा नदी में पिछले तीन महीनों के दौरान शव मिलने की यह तीसरी घटना है। इससे पहले 1 अप्रैल को जलमंदिर के समीप एक महिला का शव मिला था, जबकि 17 मई को 40 वर्षीय मजदूर बीरम वर्मा का शव नदी से बरामद हुआ था।

समग्र के कार्यों के लिए विशेष शिविर लगाए प्रतिदिन करें समीक्षा- अपर कलेक्टर

मंदसौर। मध्य प्रदेश के मंदसौर में अपर कलेक्टर एकता जायसवाल ने सोमवार को साप्ताहिक अंतर विभागीय समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि समग्र आईडी से संबंधित कार्यों के लिए विशेष शिविर लगातार आयोजित किए जाएं तथा उनकी प्रतिदिन समीक्षा की जाए। शिविरों में नवीन समग्र निर्माण एवं ई-केवाईसी के कार्य प्राथमिकता से पूर्ण किए जाएं।उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि स्कूलों में मरम्मत कार्य समय-सीमा में पूर्ण कर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें। साथ ही छात्रावास, आंगनबाड़ी भवन एवं अन्य शासकीय भवनों के मरम्मत कार्य भी वषार्काल से पूर्व पूर्ण किए जाएं। बैठक में बताया गया कि जिले में 12 जून से 18 जून 2026 तक जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से हितग्राही मूलक योजनाओं से वंचित पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। अपर कलेक्टर ने निर्देश दिए कि भूमि आवंटन के बिना कोई भी विभाग निर्माण कार्य प्रारंभ न करे। पेयजल आपूर्ति, जल गुणवत्ता परीक्षण तथा पानी की चोरी से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा संबल योजना के पंजीयन एवं अनुग्रह सहायता राशि से संबंधित लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया।बाल संरक्षण एवं महिला सशक्तिकरण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के दिए निर्देश अपर कलेक्टर एकता जायसवाल की अध्यक्षता में मिशन वात्सल्य अंतर्गत जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति तथा मिशन शक्ति की त्रैमासिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में मिशन वात्सल्य अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे स्पॉन्सरशिप योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना, आफ्टर केयर योजना एवं पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की प्रगति की समीक्षा की गई।इसके साथ ही मिशन शक्ति अंतर्गत महिला हेल्पलाइन एवं वन स्टॉप सेंटर के प्रभावी क्रियान्वयन सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।

मप्र से राज्यसभा के लिए भाजपा उम्मीदवार महेश केवट ने दाखिल किया नामांकन

तीसरी सीट के लिए रोचक हुआ मुकाबला

भोपाल। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए मुकाबला रोचक हो गया है। इस सीट के लिए भाजपा के घोषित उम्मीदवार महेश केवट ने भी आज सोमवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। अब राज्य से तीसरी सीट के लिए मुकाबला रोचक हो गया है।इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने तीसरे उम्मीदवार को भी विजय मार्ग पर लेकर चलेगी। उन्होंने कहा कि सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास-सबका प्रयास, ये हमारी पार्टी कहती नहीं बल्कि करके दिखाती है। ऐसे वर्ग, जिसके लोकसभा-विधानसभा में प्रतिनिधित्व की कमी थी, उसे सीधे उच्च सदन के लिए प्रतिनिधित्व देकर हमने प्रतिबद्धता दिखाई है। राज्यसभा के लिए नामांकन भरने से पहले महेश केवट भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे और संगठन के प्रदेश कोर कमेटी के सदस्यों, वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकताओं की उपस्थिति में पितृपुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने भाजपा कार्यालय स्थित मंदिर में पूजन अर्चन भी किया।

इस अवसर पर केवट ने कहा कि भगवान श्रीराम जब वनवास गए थे, तब उन्होंने समाज के वंचित और अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को गले लगाकर उन्हें सम्मान दिया था। भाजपा ने भी उसी विचारधारा के तहत एक सामान्य कार्यकर्ता और समाज के वंचित वर्ग से आने वाले व्यक्ति को राज्यसभा सदन जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए आगे बढ़ाया है। केवट ने कहा कि उन्होंने कभी इस जिम्मेदारी के लिए कल्पना नहीं की थी। हाल ही में उन्हें मछुआ कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था और अब पार्टी ने राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में उन पर भरोसा जताया है। इसके लिए उन्होंने पार्टी नेतृत्व और संगठन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसका पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगे।इसके बाद केवट पार्टी पदाधिकारियों के साथ दोपहर में विधानसभा पहुंचे और रिटर्निंग अधिकारी अरविंद शर्मा के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत पार्टी विधायक, विधानसभा में मौजूद रहे।

बुंदेलखंड के निवाड़ी से आने वाले महेश केवट अन्य पिछड़ा वर्ग की केवट समाज से हैं और लंबे समय से क्षेत्रीय राजनीति में सक्रिय रहे हैं। उनका नाम पहले भी चर्चा में रहा है। नगरीय निकाय चुनाव के दौरान उन पर भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार करने के आरोप लगे थे। उस समय पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के आरोपों के बीच उनको छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया था। हालांकि बाद के वर्षों में उन्होंने संगठन के साथ सक्रिय रूप से काम किया और पार्टी नेतृत्व का भरोसा फिर हासिल किया।

बालाघाट के राजवर्धन का 'लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स' में चयन

भोपाल। मध्य प्रदेश के बालाघाट की वारासिवनी तहसील के ग्राम सांवगी निवासी राजवर्धन राणा ने अपनी प्रतिभा और लगन के बल पर पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। राजवर्धन का चयन इंग्लैंड की प्रसिद्ध शिक्षण संस्था 'द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस' में 'मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन' पाठ्यक्रम के लिए हुआ है। जनसम्पर्क अधिकारी शिवम शुक्ल ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण परिवेश से निकलकर वैश्विक स्तर की इस प्रतिष्ठित संस्था तक पहुँचने में मध्यप्रदेश शासन की 'पिछड़ा वर्ग विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना' ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से सीमित किंतु होनहार विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित 'पिछड़ा वर्ग विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना' के तहत राज्य शासन राजवर्धन को पूर्ण वित्तीय सहयोग प्रदान कर रहा है। पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की फीस के रूप में 40 लाख 70 हजार 736 रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

योजना के प्रावधानों के अनुसार निर्वाह भत्ता (लिविंग अलाउंस), आकस्मिकता भत्ता, बीमा राशि और हवाई यात्रा का किराया भी राज्य शासन द्वारा वहन किया जा रहा है।राजवर्धन राणा ने अपनी इस सफलता पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर समेत पूरे प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस दूरदर्शी योजना के बिना उनके लिए इतने बड़े संस्थान में पढ़ने का सपना साकार करना संभव नहीं था। राजवर्धन ने कहा यदि लक्ष्य स्पष्ट हो, परिश्रम निष्ठापूर्वक किया जाए और शासन की योजनाओं का समुचित लाभ उठाया जाए, तो सीमित संसाधन सफलता के मार्ग में बाधा नहीं बन सकते। वे भविष्य में उच्च शिक्षा प्राप्त कर समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। जनसम्पर्क अधिकारी के अनुसार, राजवर्धन जैसे कई छात्र विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना के जरिए विदेश में पढ़ाई के अपने सपनों को साकार कर रहे हैं।

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक
तरुणमित्र
श्रम ही आधार, सिर्फ खबरों से सरोकार
मंगलवार, 9 जून 2026
विक्रम संवत्– 2083, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष, नवमी

इंडिया गठबंधन की एकजुटता!

आज 8 जून 2026 को दिल्ली के संविधान क्लब में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के अनुसार 23 सीधे और 2 आनलाइन कुल 25 पार्टियां शामिल हुईं। यह बैठक 2024 लोकसभा चुनाव के बाद और कुछ राज्य चुनावों के परिणामों के बीच हुई है। सवाल उठता है कि क्या ये 25 पार्टियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की मजबूत संगठनात्मक मशीनरी को वास्तविक टक्कर दे पाएंगी? यह सम्पादकीय इसी प्रश्न पर केंद्रित है। गठबंधन की ताकत उसकी विविधता में है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना (यूबीटी), राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियां विभिन्न राज्यों में अपनी पैठ रखती हैं। बैठक में लोकतंत्र की रक्षा, वोटर लिस्ट संशोधन, महंगाई, युवा बेरोजगारी, एजेंसियों के दुरुपयोग और संविधान पर हमलों जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। मल्लिकार्जुन खरगे ने बताया कि हर दो महीने में बैठकें होंगी, संसद सत्र में समन्वय बनेगा और आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय बैठक बुलाई जाएगी। यह प्रयास विपक्षी एकता को मजबूत करने का संकेत देता है। लेकिन हकीकत चुनौतीपूर्ण है। बैठक से पहले ही डीएमके, सीपीआई(एम) और झामुमो जैसे दलों ने अनुपस्थिति या आशंकाएं जताईं। तमिलनाडु में कांग्रेस के फैसलों से गठबंधन में दरारें दिखीं। क्षेत्रीय दल अपनी स्थानीय महत्वाकांक्षाओं को राष्ट्रीय एजेंडे से ऊपर रखते हैं। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव या स्टालिन जैसे नेता मोदी के करिश्माई नेतृत्व और भाजपा की हिंदुत्व-विकास की दोहरी रणनीति के सामने अलग-अलग लड़ते नजर आते हैं। 2024 में इंडिया गठबंधन ने 200+ सीटें जीतीं, लेकिन भाजपा-एनडीए की बहुमत वाली सरकार को रोक नहीं पाया। अब 2029 के लिए एकजुटता बनाए रखना आसान नहीं है। मोदी की ताकत व्यक्तिगत लोकप्रियता, विकास कार्यों का का प्रचार, संगठनात्मक अनुशासन और डिजिटल प्रचार में निहित है। विपक्ष अक्सर व्यक्तिगत हमलों या नकारात्मक आलोचना तक सीमित रह जाता है। जब तक इंडिया गठबंधन सकारात्मक विकल्प, रोजगार, किसान आय, सामाजिक न्याय और संघीय ढांचे की मजबूती नहीं पेश करता, जनता का विश्वास जीतना मुश्किल है। सीट शेयरिंग में झगड़े, एक-दूसरे पर आरोप और कांग्रेस की केंद्रीय भूमिका पर क्षेत्रीय दलों का असंतोष गठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी है। फिर भी, लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष जरूरी है। इंडिया गठबंधन यदि आंतरिक कलह भुलाकर मुद्दों पर फोकस करे, तो वह सरकार को जवाबदेह बना सकता है। संसद में समन्वय, राज्य स्तर पर सामूहिक अभियान और युवा-महिला-किसान केंद्रित एजेंडा सफलता की कुंजी हो सकता है। लेकिन मात्र बैठकें और प्रेस बयान काफी नहीं। जमीन पर संगठन, विचारधारा की स्पष्टता और नेतृत्व की परिपक्वता चाहिए। अंत में, 25 पार्टियां संख्या में बड़ी हैं, पर एकजुटता और रणनीति के अभाव में वे मोदी की टक्कर में कमजोर साबित हो सकती हैं। भारतीय राजनीति गठबंधनों की है, लेकिन जीत हार्दिक विश्वास और प्रदर्शन से आती है। यदि इंडिया गठबंधन अपनी कमियों को दूर कर जन-केंद्रित राजनीति अपनाए, तो 2029 रोचक हो सकता है। अन्यथा, यह बैठक भी एक औपचारिकता साबित होगी। लोकतंत्र की जीत तभी होगी जब विपक्ष सशक्त और रचनात्मक बने।

क्या भारत बूढ़ा होने की ओर बढ़ रहा है?

महेन्द्र तिवारी

भारत को लंबे समय से वैश्विक पटल पर एक ऊर्जावान और सबसे युवा आबादी वाले देश के रूप में देखा जाता रहा है। यही वह मुख्य कारण है जिसके आधार पर पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों और विचारकों ने भारत को भविष्य की एक अनिवार्य आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्वीकार किया।

देश की इस विशाल युवा आबादी को उसकी सबसे बड़ी पूंजी और सामर्थ्य माना गया क्योंकि समाज का युवा वर्ग ही उत्पादन, नए विचारों, नवाचार, श्रम शक्ति और उपभोग का सबसे बड़ा केंद्र होता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तभी गति पकड़ती है जब उसमें उपभोग करने वाले और उत्पादन करने वाले दोनों ही स्तरों पर युवाओं की सक्रिय भागीदारी हो। लेकिन हाल के समय में इस उत्साह के बीच एक नई और अत्यंत गंभीर चिंता उभरकर सामने आने लगी है।

यह चिंता जनसंख्या विस्फोट या आबादी बढ़ने की नहीं है, बल्कि जनसंख्या के भीतर बदलती आयु संरचना की है। यदि आने वाले वर्षों में देश की युवा आबादी का अनुपात लगातार घटता गया और बुजुर्गों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से तेजी से वृद्धि होती रही, तो भारत को भी निकट भविष्य में उन अभूतपूर्व समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जिनसे आज जापान, दक्षिण कोरिया और कई विकसित यूरोपीय देश अत्यंत तीव्रता से जूझ रहे हैं।

वर्तमान में उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के सांख्यिकीय आंकड़े इसी ओर संकेत कर रहे हैं कि भारत के जनसांख्यिकीय ढांचे में एक मौन परंतु बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। देश की कुल प्रजनन दर अब 2.1 के उस प्रतिस्थापन स्तर से काफी नीचे पहुंच चुकी है जिसे किसी भी समाज की जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए अनिवार्य मानक माना जाता है।

वर्ष 2025 के नवीनतम प्रतिवेदनों और आंकड़ों के अनुसार भारत की राष्ट्रीय प्रजनन दर लगभग 1.9 दर्ज की गई है, जबकि वर्ष 2014 में यही दर 2.3 के स्तर पर थी। इस सांख्यिकीय गिरावट का सीधा और स्पष्ट अर्थ यह है कि अब औसतन प्रत्येक महिला उतने बच्चों को जन्म नहीं दे रही है जितने अगली पीढ़ी में जनसंख्या के संतुलन और स्थिरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक माने जाते हैं। यह स्थिति केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर और भी अधिक असमान और चिंताजनक है। देश की राजधानी दिल्ली जैसे अत्यधिक शहरीकृत और विकसित क्षेत्रों में यह प्रजनन दर गिरकर मात्र 1.2 के स्तर तक पहुंच चुकी है जो कि अत्यंत न्यून है। अब भारत में केवल कुछ ही राज्य ऐसे बचे हैं जहां प्रजनन दर अभी भी 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर बनी हुई है, अन्यथा अधिकांश राज्यों में जन्मदर में भारी कमी देखी जा रही है।

वर्तमान समय में भारत की कुल आबादी लगभग 146 करोड़ के आसपास आंकी जा रही है और राहत की बात यह है कि देश के पास अभी भी एक बहुत बड़ी कार्यशील आयु वाली जनसंख्या मौजूद है। एक अनुमान के अनुसार भारत की लगभग 68 प्रतिशत आबादी 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग के भीतर आती है। जनसांख्यिकी विज्ञान के अनुसार यही वह मुख्य आयु वर्ग होता है जो देश की आर्थिक गतिविधियों को संचालित करता है, कर चुकाता है और संपूर्ण अर्थव्यवस्था को तीव्र गति प्रदान करता है।

लेकिन इस उत्साहजनक आंकड़े के समानांतर ही एक दूसरा सच यह भी है कि देश में 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग लोगों की संख्या भी लगातार और बहुत तेजी से बढ़ रही है। देश में बेहतर हुई स्वास्थ्य सुविधाओं, व्यापक टीकाकरण अभियानों, आधुनिक चिकित्सा तकनीक के प्रसार और आम लोगों के जीवन स्तर में हुए क्रमिक सुधार के कारण नागरिकों की औसत आयु पहले की तुलना में काफी अधिक हो गई है।

अतीत में जहां एक बड़ी आबादी उचित इलाज न मिलने या संक्रामक बीमारियों के कारण कम उम्र में ही मृत्यु का ग्रास बन जाती थी, वहीं अब चिकित्सा विज्ञान की प्रगति के कारण लोग अधिक समय तक और दीर्घायु जीवन जी रहे हैं। पहली दृष्टि में देखने पर जीवन प्रत्याशा में यह सुधार और बुजुर्गों की बढ़ती आयु अत्यंत सकारात्मक और स्वागत योग्य स्थिति प्रतीत होती है क्योंकि लंबा और स्वस्थ जीवन किसी भी सभ्य समाज और कल्याणकारी राज्य की प्रगति का सबसे बड़ा सूचकांक माना जाता है। परंतु जब देश में जन्मदर में लगातार और तीव्र गिरावट होने लगे और उसके साथ ही बुजुर्ग आबादी का अनुपात निरंतर बढ़ता जाए, तब राज्य और समाज पर अप्रत्याशित आर्थिक एवं सामाजिक दबाव बढ़ने लगते हैं। आने वाले भविष्य में देश के भीतर वास्तविक रूप से कार्य करने वाले और श्रम बल में योगदान देने वाले लोगों की संख्या आनुपातिक रूप से कम होती जाएगी, जबकि दूसरी ओर सेवानिवृत्ति वेतन, स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर पूरी तरह आश्रित रहने वाले बुजुर्ग लोगों की संख्या में भारी वृद्धि होगी। इस जनसांख्यिकीय असंतुलन का सीधा और सबसे गहरा प्रभाव सरकार के राजकोषीय खर्च, राजस्व संग्रह और संपूर्ण देश की आर्थिक विकास दर पर पड़ेगा।

भारत वर्तमान समय में वैश्विक मंचों पर जिस जनसांख्यिकीय लाभांश की बात अत्यंत गर्व के साथ करता है, वह कोई स्थायी वरदान नहीं है और न ही यह हमेशा के लिए रहने वाला है। यदि देश की इस वर्तमान युवा आबादी को समय रहते गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक कौशल प्रशिक्षण और उनकी योग्यता के अनुसार पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं कराए गए, तो यही लाभांश भविष्य में देश के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक और सामाजिक बोझ बन सकता है। देश में बेरोजगारी की समस्या पहले से ही एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में विद्यमान है।

यदि आने वाले दशकों में देश का कम संख्या वाला युवा कार्यबल अपने से कई गुना अधिक बुजुर्ग आबादी का आर्थिक भार उठाने के लिए मजबूर होगा, तो इससे न केवल युवाओं पर करों का बोझ बढ़ेगा बल्कि देश के आर्थिक विकास की गति भी अत्यंत धीमी पड़ जाएगी। कार्यशील लोगों की कमी के कारण उद्योगों में उत्पादन प्रभावित हो सकता है और नए विचारों के क्रियान्वयन की गति मंद हो सकती है।

आर्थिक मोर्चे के साथ-साथ देश की संपूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी बुजुर्ग आबादी के इस बढ़ते बोझ का बेहद गंभीर और दूरगामी असर पड़ेगा। जैसे-जैसे समाज में वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ेगी, वैसे-वैसे आयु से संबंधित बीमारियां जैसे हृदय रोग, मधुमेह, कर्क रोग, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विकार और विस्मृति जैसी समस्याएं अत्यंत तीव्र गति से बढ़ेंगी।

इन बीमारियों के प्रबंधन और उपचार के लिए देश को बहुत बड़े स्तर पर विशेषीकृत चिकित्सालयों, वृद्धावस्था देखभाल केंद्रों, इस कार्य के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों और एक मजबूत सामाजिक सहायता तंत्र की आवश्यकता होगी। भारत की वर्तमान स्वास्थ्य अवसंरचना को यदि देखा जाए, तो वह अभी भी विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में उतनी मजबूत और पर्याप्त नहीं है जितनी होनी चाहिए। यदि हमने आज से ही इस जनसांख्यिकीय बदलाव को भांपकर अपनी चिकित्सा प्रणालियों में सुधार और व्यापक तैयारियां शुरू नहीं कीं, तो भविष्य में देश के सामने एक अत्यंत गहरा स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हो सकता है।

सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर भी इस जनसांख्यिकीय परिवर्तन के बहुत गहरे और संवेदनशील प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले हैं। सदियों पुरानी पारंपरिक भारतीय संयुक्त परिवार व्यवस्था समकालीन समय में बहुत तेजी से बदल रही है और उसका स्थान अब एकल या छोटे परिवारों ने ले लिया है।

ये लेखक के अपने विचार हैं तरुणमित्र का इससे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

भारत की जनसंख्या में ऐतिहासिक बदलाव

डॉ. जगदीप सिंह

भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की कुल प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे पहुंच गई है। राष्ट्रीय स्तर पर यह दर अब औसतन एक दशमलव नौ बच्चों तक सीमित हो गई है जबकि कुछ समय पहले यह दो दशमलव तीन थी। प्रतिस्थापन स्तर वह सीमा है जिसमें एक महिला औसतन दो दशमलव एक बच्चे को जन्म दे तो आबादी स्थिर बनी रहती है।

अब इस सीमा से नीचे जाने के कारण देश की आबादी भविष्य में लगातार घटने लगेगी। दिल्ली जैसे बड़े शहर में यह दर मात्र एक दशमलव दो तक पहुंच गई है जो कई विकसित राष्ट्रों से भी कम है। यह आंकड़ा विकास की उपलब्धि है परंतु साथ ही आने वाले समय की कई चुनौतियों की ओर इशारा भी करता है।

यह परिवर्तन अचानक नहीं आया। पिछले कई वर्षों में देशभर में परिवार नियोजन के प्रयासों ने प्रभाव दिखाया है। पहले के वर्षों में प्रजनन दर काफी ऊंची थी परंतु शिक्षा के प्रसार और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार ने इसे तेजी से घटाया। कई राज्यों में यह प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है जबकि कुछ क्षेत्रों में अभी भी थोड़ी ऊंची बनी हुई है।

शहरी इलाकों में यह दर और कम है क्योंकि वहां जीवन व्यय अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा और जागरूकता बढ़ने से परिवार छोटे हो रहे हैं। महिलाओं की साक्षरता ने सबसे बड़ा योगदान दिया है क्योंकि पढ़ी लिखी महिलाएं विवाह में देरी करती हैं और कम संतानों को जन्म देना पसंद करती हैं। शहरीकरण ने इस बदलाव को और गति दी। शहरों में बच्चों की देखभाल की लागत बढ़ गई है। शिक्षा का खर्च आवास की समस्या और स्वास्थ्य सुविधाएं महंगी हो गई हैं। युवा जोड़े अब करियर और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देते हैं। वे छोटे परिवार को अधिक आरामदायक मानते हैं। आर्थिक प्रगति के साथ मध्यम वर्ग का विस्तार हुआ है। युवा पीढ़ी सोशल मीडिया और वैश्विक प्रभावों से प्रभावित होकर पारंपरिक परिवार व्यवस्था से अलग सोच रखती है। परिणामस्वरूप कई दंपत्ति एक या दो बच्चों तक ही सीमित रह रहे हैं। इससे मां और बच्चे दोनों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हुआ है। दक्षिण के कई राज्य लंबे समय से इस राह पर चल रहे हैं। वहां शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर सूचकांक ने प्रजनन दर को नियंत्रित किया। राजधानी दिल्ली का उदाहरण विशेष है जहां व्यस्त जीवनशैली कामकाजी महिलाओं की अधिकता और सीमित जगह ने परिवारों को छोटा रखने को मजबूर किया। इसके विपरीत कुछ उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में दर अभी भी अपेक्षाकृत ऊंची है परंतु राष्ट्रीय औसत नीचे खिसक गया है। यह असमानता देश की विविधता को दिखाती है। विकास के साथ जनसंख्या नियंत्रण स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है।

इस गिरावट के सकारात्मक प्रभाव कई क्षेत्रों में दिखेंगे। संसाधनों पर दबाव कम होगा। पानी भोजन ऊर्जा और पर्यावरण की सुरक्षा बेहतर बनी रहेगी। शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति व्यय बढ़ेगा जिससे मानव संसाधन मजबूत होंगे। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी जो समग्र विकास को गति देगी।

अभी कुछ वर्षों तक कार्यशील उम्र की आबादी का लाभ मिलेगा जो अर्थव्यवस्था को सहारा देगा। परंतु चुनौतियां भी सामने आएंगी। आबादी घटने से श्रम बल का आकार सिकुड़ेगा। वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ेगी और उनकी देखभाल का बोझ समाज पर पड़ेगा। पेंशन व्यवस्था स्वास्थ्य सेवाएं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए नई योजनाएं बनानी होंगी। स्कूलों में छात्र संख्या घटेगी जिससे शिक्षा प्रणाली को अनुकूलित करना पड़ेगा। उद्योग सेना और सेवा क्षेत्रों में कार्यकताओं की कमी महसूस हो सकती है। इन समस्याओं से निपटने के लिए तैयारी अभी से शुरू करनी चाहिए। आर्थिक दृष्टि से देखें तो उत्पादकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना होगा। रोबोटिक्स कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कौशल विकास कार्यक्रमों से काम पूरा किया जा सकता है। महिलाओं को कार्यबल में अधिक शामिल करने के लिए बाल देखभाल केंद्र बढ़ाने पड़ेंगे। वृद्धजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल मजबूत करना आवश्यक है। अनुमान बताते हैं कि कुछ दशकों बाद आबादी चरम पर पहुंचकर घटने लगेगी। इस संक्रमण को सुचारू बनाने के लिए नीतियां सोच समझकर बनानी होंगी। दुनिया के अन्य देश भी इसी स्थिति से गुजर रहे हैं। कई विकसित राष्ट्रों में प्रजनन दर लंबे समय से कम है। वहां वृद्ध आबादी की समस्या गहरी हो गई है। भारत अपनी विशाल संख्या के कारण वैश्विक प्रभाव रखता है। अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से सीखकर अपनी राह बनानी चाहिए। कुछ देशों ने परिवार समर्थन नीतियां अपनाकर सफलता पाई है।

ये लेखक के अपने विचार हैं तरुणमित्र का इससे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

अस्तित्व भी बचाना है !

कृष्णेन्द्र राय

बैठक की तुम कोशिश करना ।
पर कभी साथ न रहना ।।
अस्तित्व भी बचाना है ।
अस्तित्व भी बचाना है ।।
जब करना हो चाय-पकौड़ा ।
पास सभी आ जाना ।।
हरकत को हमारी भी । निहार रहा ये जमाना ।।
लेकिन दूल्हा तय करने की ।
कभी न कोशिश करना ।।
सपना तो टूट जाता है ।
सपना तो टूट जाता है ।।
होती हैं बेदर्द बहुत ही । राजनीति की रस्में ।।
मुश्किल कर देतीं हैं निभाना ।
आपस की ये कसमें ।।
अपनी-अपनी लिस्ट लेकर । टेबल से ना गुजरना ।।
टेबल ये रुठ जाता है । टेबल ये रूठ जाता है ।।

कोचिंग उद्योग का विस्तार शिक्षा व्यवस्था की असफलता का प्रमाण तो नहीं!

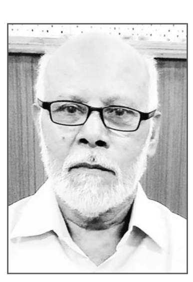

संतराम पाण्डेय

भारत में शिक्षा का विषय हमेशा से ही चर्चा का केंद्र रहा है। 'शिक्षा ही समाज की आधारशिला है' जैसी कहावतें हमें बचपन से सुनाई जाती हैं, लेकिन असलियत में यह आधारशिला कितनी मजबूत है, यह आज सवालों के घेरे में है। स्कूलों में पढ़ाई, शिक्षक, पाठ्यक्रम और परीक्षा-इन सब पर नजर डालें तो स्पष्ट होता है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली बच्चों के लिए कई तरह की चुनौतियाँ पैदा कर रही है। कई बार ऐसा लगता है कि शिक्षा प्रणाली अपने मूल उद्देश्य से भटक गई है।

सरकारें समय-समय पर शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करती आ रही हैं लेकिन अभी वह लक्ष्य नहीं मिल पा रहा है जो शिक्षा के लिए जरूरी है। आज भी बच्चों को ज्ञान देने के बजाय उन्हें परीक्षा में अंक हासिल करने की मशीन बना दिया गया है। बच्चा सुबह स्कूल जाता है, दोपहर बाद कोचिंग और शाम को होमवर्क में उलझ जाता है। बचपन, खेल, रचनात्मकता और मानसिक संतुलन धीरे-धीरे इस दौड़ में दम तोड़ देते हैं। दूसरी तरफ कोचिंग संस्थानो का एक और रूप सामने आ रहा है।

संचालक इतने मजबूत हो गए हैं कि अब वह शिक्षा, परीक्षा और व्यवस्था को प्रभावित करने लगे हैं। साठ दशक पार कर चुके लोग कहते सुने जाते हैं कि हमारे जमाने में तो कोचिंग नहीं थी, फिर भी हम अच्छा पढ़ते थे। बच्चों के जीवन में कोचिंग संस्थानों का स्थान शिक्षा प्रणाली के विकार को उजागर करता है। जब स्कूल खुद परीक्षा के लिए बच्चों को तैयार नहीं कर पाते, तो माता-पिता मजबूरन कोचिंग की ओर रुख करते हैं। यही वह जगह है जहाँ 'शिक्षा माफिया' का रूप सामने आता है। कोचिंग संचालक कभी-कभी बच्चों और माता-पिता की उम्मीदों का फायदा उठाकर भारी शुल्क वसूलते हैं, और शिक्षा का उद्देश्य केवल अंक और सफलता तक सीमित रह जाता है।

कोचिंग की इस संस्कृति ने बच्चों के जीवन में तनाव और प्रतिस्पर्धा को अत्यधिक बढ़ा दिया है। बच्चे मानसिक दबाव के कारण पढ़ाई से घृणा करने लगते हैं, जबकि उनका मूल जिज्ञासु मन कहीं दबकर रह जाता है। कोटा का कोचिंग उद्योग हो या शहरों व कस्बों में गली-गली में उग रहे कोचिंग संस्थान, इससे बच्चे का जिज्ञासु मन प्रभावित हुआ है। कभी शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा साधन माना जाता था। कहा जाता था कि स्कूल वह जगह है जहाँ बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उनके भीतर ज्ञान, संस्कार और सोचने-समझने की क्षमता विकसित होती है। लेकिन आज के दौर में यदि कोई अभिभावक अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर चिंतित दिखाई देता है तो उसके पीछे ठोस कारण हैं। स्कूलों में पढ़ाई का स्तर लगातार सवालों के घेरे में है, कोचिंग संस्थानों का ऐसा जाल फैल चुका है कि शिक्षा अब सेवा नहीं, बल्कि एक बड़ा कारोबार बनकर रह गई है। स्कूल और छात्र के बीच कोचिंग का प्रवेश कब हो गया, इसका भान न स्कूलों को हुआ, न अभिभावकों को। परिणामस्वरूप आज इसका खमियाजा बच्चे उठा रहे हैं। हालात यह हैं कि लाखों रुपये फीस लेने वाले स्कूल भी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का भरोसा नहीं दिला पा रहे। दूसरी ओर सरकारी स्कूलों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर बच्चे पढ़ें तो पढ़ें कैसे? शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि स्कूल अब शिक्षा के केंद्र कम और परीक्षा परिणामों के केंद्र अधिक बन गए हैं। बच्चों को विषय समझाने के बजाय उन्हें परीक्षा में अच्छे अंक लाने की तकनीक सिखाई जाती है। स्थिति इतनी चिंताजनक हो चुकी है कि कई स्कूलों में शिक्षक भी यह मानकर चलते हैं कि असली तैयारी तो कोचिंग संस्थानों में ही होगी। यानी स्कूल की फीस अलग, कोचिंग की फीस अलग। कोचिंग उद्योग का विस्तार अपने आप में शिक्षा व्यवस्था की असफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। यदि स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो रही होती तो करोड़ों रुपये का कोचिंग बाजार खड़ा ही नहीं होता। आज छोटे शहरों से लेकर महानगरों तक कोचिंग संस्थानों की भरमार है। हर गली में एक नया संस्थान खुल रहा है और हर संस्थान खुद को सफलता की गारंटी बताने में जुटा है। दुर्भाग्य यह है कि कई जगह यह उद्योग अब माफिया संस्कृति का रूप ले चुका है।

भारी फीस, आकर्षक विज्ञापन, फर्जी दावे और टॉपरों के नाम पर प्रचार का खेल खुलेआम चल रहा है। अभिभावकों की मजबूरी और बच्चों के भविष्य की चिंता एक बाजार में बदल गया है। शिक्षा को सेवा नहीं, उत्पाद की तरह बेचा जा रहा है। सबसे अधिक नुकसान बच्चों को हो रहा है।

उन पर कम उम्र में ही सफलता का ऐसा दबाव डाल दिया जाता है कि वे जीवन को अंकों और रैंकिंग के चश्मे से देखने लगते हैं। यदि अच्छे अंक आ गए तो बच्चा प्रतिभाशाली, नहीं आए तो वह असफल घोषित कर दिया जाता है। यह सोच न केवल गलत है बल्कि खतरनाक भी है।

आज हजारों बच्चे तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। प्रतियोगिता की अंधी दौड़ ने उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाला है। कई बच्चों को यह तक समझ नहीं आता कि वे पढ़ाई अपने ज्ञान के लिए कर रहे हैं या केवल किसी परीक्षा में दूसरों से आगे निकलने के लिए। शिक्षा का मूल उद्देश्य कहीं पीछे छूट गया है। विडंबना यह भी है कि शिक्षा नीतियों और सुधारों की घोषणाएं तो लगातार होती रहती हैं, लेकिन जमीन पर बदलाव की रफ्तार बेहद धीमी है। स्मार्ट क्लास, डिजिटल शिक्षा और नई तकनीकों की बातें खूब होती हैं, मगर कई स्कूल आज भी बुनियादी शिक्षण गुणवत्ता के संकट से जूझ रहे हैं। शिक्षा के नाम पर योजनाएं बनती हैं, बजट खर्च होते हैं, रिपोर्टें तैयार होती हैं, लेकिन कक्षा में बैठा बच्चा अक्सर वही पुरानी समस्याएं झेलता रहता है।

जरूरत इस बात की है कि शिक्षा को फिर से शिक्षा बनने दिया जाए। स्कूलों को इतना सक्षम बनाया जाए कि बच्चे और अभिभावक कोचिंग के सहारे रहने को मजबूर न हों। शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जाए। पाठ्यक्रम को ऐसा बनाया जाए जो बच्चों को सोचने, समझने और सवाल पूछने के लिए प्रेरित करे।

कोचिंग संस्थानों पर भी प्रभावी निगरानी की आवश्यकता है। शिक्षा के नाम पर मनमानी फीस वसूलने और भ्रामक दावे करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

यदि शिक्षा बाजार के हवाले कर दी जाएगी तो गरीब और मध्यम वर्ग के लाखों बच्चों के लिए अवसरों की समानता केवल एक सपना बनकर रह जाएगी। ध्यान रहे कि शिक्षा किसी भी देश की रीढ़ होती है। यदि वही कमजोर पड़ जाए तो भविष्य भी कमजोर हो जाता है।

ये लेखक के अपने विचार हैं तरुणमित्र का इससे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

आज का राशिफल

मेष– शैक्षणिक कार्य आसानी से पूरे होते रहेंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। परिश्रम प्रयास से काम बनाने की कोशिश लाभ देगी। व्यापार व व्यवसाय में ध्यान देने से सफलता मिलेगी। बुरी संगति से बचें।

वृष– अपने अधीनस्थ लोगों से कम सहयोग मिलेगा। बाहरी सहयोग की अपेक्षा रहेगी। सलाह उपयोगी सिद्ध होगी। विपरीत परीस्थितियों में भी हानि नहीं होगी। पठन-पाठन में स्थिति कमजोर रहेगी।

मिथुन– व्यापार व नौकरी में स्थिति अच्छी रहेगी। आलस्य का त्याग करें। कार्यसिद्धि होने में देर नहीं लगेगी। आर्थिक लाभ उत्तम रहेगा। शैक्षणिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।

कर्क– समय पक्ष का बना रहेगा। कारोबारी काम में प्रगति बनती रहेगी। लेन-देन में आ रही बाधा दूर करने का प्रयास होंगे। धार्मिक कार्य में समय और धन व्यय होगा। पुराने मित्र से मिलन होगा।

सिंह– मेहमानों का आगमन होगा। राजकीय कार्यों से लाभ। पैतृक सम्पत्ति से लाभ। विद्यार्थियों को लाभ। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। कारोबारी काम में नवीन तालमेल और समन्वय बन जाएगा।

कन्या– जीवनसाथी अथवा यार-दोस्तों के साथ साझे में किए जा रहे काम में लाभ मिल जाएगा। एकाकी वृत्ति त्यागें। हित के काम में आ रही बाधा मध्याह्न पश्चात दूर हो जाएगी।

तुला– प्रसन्नता के साथ सभी जरूरी कार्य बनते नजर आएंगे। मनोरथ सिद्धि का योग है। सभा-गोष्ठियों में सम्मान मिलेगा। प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कुछ सामाजिक कार्य संपन्न होंगे।

वृश्चिक– स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार की अपेक्षा रहेगी। ज्ञान-विज्ञान की वृद्धि होगी और सज्जनों का साथ भी रहेगा। कुछ कार्य भी सिद्ध होंगे। व्यर्थ की दौड़-भाग से यदि बचा जाए तो अच्छा है।

धनु– आशा और उत्साह के कारण सक्रियता बढ़ेगी। आगे बढने.के अवसर लाभकारी सिद्ध होंगे। कोई प्रिय वस्तु या नवीन वस्त्राभूषण प्राप्त होंगे। सभाओं में मान-सम्मान बढ़ेगा।

मकर– लेन-देन में आ रही बाधा को दूर करने के प्रयास सफल होंगे। धार्मिक कार्य में समय और धन व्यय होगा। कारोबारी काम में बाधा बनी रहेगी। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। व्यापार में स्थिति नरम रहेगी।

कुंभ– पूर्व नियोजित कार्यक्रम सरलता से संपन्न हो जाएंगे। जोखिम से दूर रहना ही बुद्धिमानी होगी। ले देकर की जा रही काम की कोशिश ठीक नहीं। आशा और उत्साह के कारण सक्रियता बढ़ेगी।

मीन– लाभ में आशातीत वृद्धि तय हैं मगर नकारात्मक रुख न अपनाएं। किसी पुराने संकल्प को पुरा कर लेने का दिन हैं।

पं0 सुभाष पाण्डेय: हस्तरेखा विशेषज्ञ, मो. 8808052918

सूडोकु नवताल- 7820

★☆☆☆☆ सरल

5	9			3			8	7
8	7		1		5			
		2			9			4
	6				2		3	5
3	8		4	1	7		2	9
2	4		6				1	
7			3			8		
			5		8		7	3
9	3			2			6	1

Jagrutidaur.com, Bangalore

- *प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.*
- *प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.*
- *पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.*
- *पहेली का केवल एक ही हल है.*

सूडोकु नवताल -7819 का हल

7	4	8	3	9	2	1	5	6
2	6	9	5	7	1	8	4	3
3	1	5	4	8	6	7	2	9
5	7	4	8	6	9	3	1	2
8	9	1	2	3	4	6	7	5
6	3	2	1	5	7	4	9	8
4	8	7	6	2	5	9	3	1
9	2	6	7	1	3	5	8	4
1	5	3	9	4	8	2	6	7

100 साल पुराने नत्थूजी जगताप स्कूल के नए भवन की मांग

सुशासन तिहार शिविर में सौंपा आवेदन

धमतरी। सुशासन तिहार के तहत आम जनता की समस्याओं के समयबद्ध निराकरण और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से नत्थूजी जगताप हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में रिसाईपारा पूर्व-पश्चिम, नयापारा और टिकरापारा वार्ड के नागरिकों ने विभिन्न समस्याओं और मांगों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए।

इसी दौरान नत्थूजी जगताप हायर सेकेंडरी स्कूल की शाला विकास प्रबंधन समिति ने विद्यालय की जर्जर और लगभग 100 वर्ष पुरानी भवन संरचना को ध्वस्त कर नए भवन के निर्माण की मांग को प्रमुखता से उठाया। समिति अध्यक्ष मुकेश शर्मा तथा सदस्य कुंदन ठाकुर और दमलेश कोसरिया ने अधिकारियों को आवेदन सौंपते हुए बताया कि विद्यालय भवन अपनी आयु पूरी कर चुका है और वर्तमान में विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि भवन में लगे पुराने शेड के कारण गर्मी के दिनों में कक्षाओं का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है, जिससे छात्रों को पढ़ाई में परेशानी होती है। वहीं भवन में प्रयुक्त लकड़ियों को दीमक लगातार नुकसान पहुंचा रही है और कई हिस्सों की लकड़ी कमजोर होकर टूटने की स्थिति में पहुंच चुकी है।

समिति ने कहा कि भवन वर्षों पुराना होने के कारण उसकी मजबूती लगातार कम हो रही है, इसलिए किसी संभावित दुर्घटना से पहले इसे डिस्मेंटल कर आधुनिक सुविधाओं से युक्त नया भवन बनाया जाना आवश्यक है। आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया कि यह विद्यालय शहर की महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थाओं में शामिल है और लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। विद्यालय के विद्यार्थी बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर परिणाम दे रहे हैं तथा सांस्कृतिक गतिविधियों, खेलकूद, स्काउट और एनसीसी जैसे क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर तक अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बावजूद विद्यालय को आधारभूत सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। समिति ने विद्यालय परिसर की सुरक्षा के लिए चौकीदार की नियुक्ति, नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा परिसर में मौजूद पुराने, जर्जर और आग से क्षतिग्रस्त भवनों को तत्काल हटाने की मांग भी रखी। समिति सदस्यों ने कहा कि विद्यालय में अध्ययनरत अधिकांश छात्र गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों से आते हैं, जिन्हें सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना शासन और समाज दोनों की जिम्मेदारी है। उनका कहना है कि नया भवन बनने से न केवल विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि 100 वर्ष पुराने इस विद्यालय को उसका खोया गौरव भी वापस मिल सकेगा।

धमतरी में रोजगार मेला 11 जून को, 357 पदों पर होगी भर्ती

धमतरी। जिले के शिक्षित एवं रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर लेकर 11 जून को लाईवलीहुड कॉलेज, धमतरी में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा।

जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित इस मेले में विभिन्न प्रतिष्ठित निजी संस्थानों द्वारा सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, हाउसकीपिंग स्टाफ सहित कुल 357 पदों पर भर्ती की जाएगी। सहायक परियोजना अधिकारी ने सोमवार को बताया कि रोजगार मेले में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पांचवीं एवं दसवीं उत्तीर्ण निर्धारित की गई है। इच्छुक युवा अपने शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार के फोटो तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने जिले के युवाओं से रोजगार मेले का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और इस तरह के आयोजनों से निजी क्षेत्र में बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं। रोजगार मेले में अभ्यर्थियों का प्रारंभिक पंजीयन, साक्षात्कार तथा पात्रतानुसार चयन की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी पात्र एवं इच्छुक युवाओं से समय पर पहुंचकर रोजगार के इस अवसर का लाभ उठाने का आग्रह किया है।

राज्यपाल से अखिल भारतीय गोंड़वाना गोंड़ महासभा के पदाधिकारियों ने की भेंट

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका से आज सोमवार को लोकभवन में अखिल भारतीय गोंड़वाना गोंड़ महासभा के राष्ट्रीय सचिव आरएन ध्रुव के नेतृत्व में समाज के प्रतिनिधियों ने सौजन्य भेंट की। उन्होंने ग्राम गोंड़ खपरी जिला धमतरी में ग्रामीणों के श्रम दान से निर्मित सिंचाई परियोजना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित गोल्डन जुबली कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल को आमंत्रित किया।

इस अवसर पर एसपी ध्रुव, नारायण ध्रुव और रामनरेश भी उपस्थित थे।

संक्षिप्त समाचार

मानिकपुर गांव में लगाए गए कई प्रजाति के पौधे

कोरबा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन मण्डल कटघोरा के वन परिक्षेत्र चेतमा के मानिकपुर परिसर कक्ष क्रमांक रोपड़ स्थल में छत्रपाल सिंह राज सरपंच संघ अध्यक्ष जिला कोरबा के मुख्य आतिथ्य में एवं जनपद सदस्य श्रीमती इंद्रा पटेल, सांसद प्रतिनिधि डी के आदिले, सरपंच चैतमा राजलाल सिन्दराम, सरपंच मानिकपुर जयसिंह आयाम, उप सरपंच चैतमा सुकालु प्रजापति, पूर्व सरपंच गिरीश कुमार पारसे, सामाजिक कार्यकर्ता शेख इसरार, वन अधिकार अध्यक्ष मुरितराम, उपाध्यक्ष राकेश पारसे, वन प्रबंधन समिति अध्यक्ष श्रीमति मंजू देवी, उपाध्यक्ष सोहनदास, पंच किताब सिं एवं वन परिक्षेत्र चेतमा के कर्मचारी और ग्रामीण जनों की उपस्थिति में पौधा रोपड़ का कार्य किया गया। साथ ही अतिथियों एवं ग्रामीणों को विभिन्न प्रजातियों के पौधों का वितरण कर पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षारोपण के प्रति जागरूक किया गया।कार्यक्रम में सभी उपस्थितजनों ने पर्यावरण संरक्षण एवं हरित आवरण बढ़ाने का संकल्प लिया।

भाजपा कुदमुरा मंडल ने रजगामार में किया पौधों का रोपण

कोरबा। पर्यावरण दिवस पर भाजपा कुदमुरा मंडल ने रजगामार में कुछ प्रजातियों के पौधों का रोपण करने के साथ इसका संरक्षण करने का संकल्प दोहराया। रजगामार मे पर्यावरण दिवस पर उपसरपंच श्रीमती पूनम चैरसिया, वार्ड क्रमांक 15 के पंच श्रीमती पुष्पा सिंह मरावी, श्रीमती शारदा बाई उइके, वार्ड क्रमांक 09 के पंच व एनजीओ प्रकोष्ठ के प्रदेश सहसंयोजक अज्ञात यादव, भाजपा कुदमुरा मंडल के महामंत्री कौशल चैरसिया, वार्ड क्रमांक 8 के पंच श्रीमती राधा नेताम, मुकेश नेताम व अन्य ग्रामीण जनों ने पर्यावरण दिवस पर ओमपुर स्टेडियम में वृक्षारोपण किया। उन्होंने संकल्प लिया की इन पौधों की रक्षा हमें करना है क्योंकि वर्धा से ही पर्यावरण में शुद्धता होती है जो हमारे जीवनदायनी है। जहां कहीं भी पर्यावरण संतुलन की स्थिति है उसके खतरे हर कोई महसूस कर रहा है और बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित हो रहा है। इसलिए हमें पर्यावरण को बड़े परिपेक्ष में समझने की आवश्यकता है। यह स्वीकार करना होगा कि पर्यावरण से ही जीवन है और जीवन को सुनिश्चित करने के लिए सभी लोग अपने नागरिक कर्तव्य का निर्वहन जरूर करेंगे।

सियान गुड़ी डे केयर सेन्टर का हुआ उद्घाटन

अम्बिकापुर सरगुजा। अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ सरकार की विशेष पहल के तहत राज्य के विभिन्न हिस्सों में बुजुर्गों के लिए सियान गुड़ी की शुरूआत की जा रही है। इसी कड़ी में सरगुजा जिले के प्रभारी एवं प्रदेश के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अंबिकापुर में नए सियान गुड़ी डे-केयर सेंटर का उद्घाटन किया। इस केंद्र में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मनोरंजन से लेकर हर प्रकार की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। प्रभारी मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि हमारे सम्मानीय बुजुर्ग समाज की अनमोल धरोहर हैं। ओल्ड इज गोल्डइ की कहावत ऐसे ही नहीं बनी है बुजुर्गों के गहरे अनुभव से ही हमारी आने वाली पीढ़ी बेहतर सीख ले सकती है। उनके मार्गदर्शन में ही एक मूल्यवान और सशक्त समाज का निर्माण संभव है। इसलिए हर समाज में बुजुर्गों का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए।

सपना हुआ साकार-प्रधानमंत्री आवास ने बदली मसूराम सेठिया के परिवार की जिंदगी

जगदलपुर। जिले के तोकापाल विकासखंड के ग्राम छापर भानपुरी निवासी मसूराम सेठिया के लिए पक्के मकान का सपना कभी दूर की बात लगता था। सीमित आय और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच जीवन यापन कर रहे मसूराम ने कभी नहीं सोचा था कि उनका परिवार भी एक सुरक्षित और सुविधायुक्त घर में रह सकेगा। लेकिन शासन की प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनके इस सपने को साकार कर दिया है।

करीब एक एकड़ कृषि भूमि पर खरीफ सीजन में धान की खेती और वर्षभर मजदूरी कर अपने छह सदस्यीय परिवार का भरण-पोषण करने वाले मसूराम वर्षों तक कच्चे मकान में रहने को मजबूर थे। बरसात के दिनों में छत टपकने, दीवारों में सीलन और मौसम की मार झेलने जैसी समस्याएं उनके परिवार की दिनचर्या का हिस्सा थीं। ऐसे में पक्का मकान बनवाना उनकी आर्थिक क्षमता से बाहर था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिली सहायता से मसूराम का घर अब मजबूत और सुरक्षित बन चुका है। नए घर में रहने के बाद परिवार के सदस्यों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। मसूराम बताते हैं कि अब उन्हें बारिश, आंधी और अन्य मौसम संबंधी परेशानियों की चिंता नहीं रहती। परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित वातावरण में रह रहे हैं, जिससे मानसिक संतोष भी मिला है।

योजना का लाभ मिलने के बाद मसूराम ने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए अपनी बचत राशि से घर में दो अतिरिक्त कमरे बनाने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि बेटा-बहू और दो नाती परिवार के साथ रहते हैं, इसलिए बढ़ते परिवार के लिए पर्याप्त स्थान होना जरूरी है। अतिरिक्त कमरों के निर्माण से परिवार को और अधिक सुविधा मिलेगी तथा सभी सदस्य आरामदायक जीवन व्यतीत कर सकेंगे। मसूराम सेठिया का मानना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने न केवल उन्हें पक्का घर दिया है, बल्कि उनके परिवार को सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य का भरोसा भी दिया है।

जिले में 41 समाधान शिविरों के माध्यम से कुल 35 हजार 470 आवेदन मिले

70 प्रतिशत आवेदनों का हुआ निराकरण, शेष आवेदनों का समयबद्ध निराकरण किया जा रहा

महासमुंद। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप प्रदेशभर में आयोजित सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत महासमुंद जिले में जनसमस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के लिए आयोजित समाधान शिविर सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।

कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में जिले के विभिन्न विकासखंडों में कुल 41 समाधान शिविरों का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों एवं आमजनों ने अपनी मांगों, समस्याओं एवं शिकायतों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर श्री लंगेह ने संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए लंबित आवेदनों का शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

सुशासन तिहार के दौरान जिले में 01 मई से 05 जून 2026 तक कुल 35 हजार 470 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें 34 हजार 411 मांग संबंधी आवेदन तथा 360 शिकायत संबंधी आवेदन शामिल हैं। प्राप्त आवेदनों में से अब तक 24 हजार 725 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है, जो कुल प्राप्त आवेदनों का लगभग 70 प्रतिशत है। शेष 10 हजार 745 लंबित आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया तेजी से जारी है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय अपने औचक निरीक्षण के दौरान कमरौद में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। वहीं जिले के प्रभारी मंत्री एवं खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, सांसद रूपकुमारी चौधरी शिविरों में शामिल हुए। साथ ही क्षेत्रीय विधायक गण एवं जनप्रतिनिधियों की भी गरिमामयी उपस्थिति रही। जनप्रतिनिधियों द्वारा हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृति पत्र, सामग्री एवं अन्य लाभों का वितरण किया गया। अनेक हितग्राहियों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ मिलने से उनके चेहरे पर संतोष और खुशी देखने को मिली। समाधान शिविरों में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई तथा पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही लाभान्वित किया गया। शिविरों में राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आयुष्मान कार्ड, किसान कल्याण योजनाएं, राजस्व प्रकरण, विद्युत, पेयजल, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े आवेदनों का निराकरण प्राथमिकता से किया गया। संवाद से समाधान का उद्देश्य हुआ पूर्ण सुशासन तिहार के दौरान बागबाहरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत कमरौद में मुख्यमंत्री की घोषणा के मात्र 10 दिवस के भीतर ही मुक्तिधाम निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। शासन-प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। इसी तरह आंवराडबरी बनवासी श्री खोमनलाल साहू की समस्या का मौके पर ही समाधान करते हुए आबादी पट्टा तैयार कर उन्हें सौंपा गया। मालिकाना हक मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का धन्यवाद ज्ञापित किया। शिविर में राहुल एवं खोमन को मौके पर ही लर्निंग लाइसेंस जारी होने पर वे बेहद खुश नजर आए। इस त्वरित समाधान के लिए उन्होंने शासन एवं प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

भटगांव में नशा उन्मूलन अभियान को मिला जनसमर्थन

धमतरी। अखिल विश्व गायत्री परिवार धमतरी के तत्वावधान में ग्राम भटगांव में चल रहे सात दिवसीय नशा उन्मूलन जनजागरूकता अभियान को ग्रामीणों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। 3 जून से प्रारंभ होकर 9 जून तक आयोजित इस विशेष अभियान का उद्देश्य समाज को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा युवाओं को स्वस्थ, संस्कारित और सकारात्मक जीवन की ओर प्रेरित करना है।

अभियान के तहत प्रतिदिन विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। इसी क्रम में सोमवार को भटगांव के बाजार चौक में एक कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार और आध्यात्मिक वातावरण के बीच संपन्न हुए इस आयोजन में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए तथा समाज को नशामुक्त बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि नशा केवल व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। इसलिए इसके खिलाफ सामूहिक प्रयास और जनभागीदारी अत्यंत आवश्यक है।

प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के कौशल प्रसाद साहू ने बताया कि गायत्री परिवार द्वारा लंबे समय से नशा उन्मूलन, नैतिक जागरण और सामाजिक सुधार के लिए निरंतर अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने और उन्हें रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से यह अभियान संचालित किया जा रहा है। ग्राम पंचायत भटगांव के सरपंच फागू राम साहू ने गायत्री परिवार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम सामाजिक और आध्यात्मिक एकता को मजबूत करने के साथ-साथ समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने ग्रामीणों से नशामुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने की अपील की।

अभियान के समापन अवसर पर मंगलवार 9 जून को शाम 3 बजे ग्राम भटगांव में विशाल नशा उन्मूलन रैली निकाली जाएगी। यह रैली गांव की विभिन्न गलियों से होकर गुजरेगी और लोगों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करेगी। रैली के पश्चात बाजार चौक में सभा का आयोजन होगा, जिसमें नशामुक्त समाज के निर्माण और युवा पीढ़ी को सकारात्मक दिशा देने पर विचार व्यक्त किए जाएंगे।

मंत्री केदार कश्यप ने साहित्यकारों के सम्मान के साथ तीन किताबों का किया विमोचन

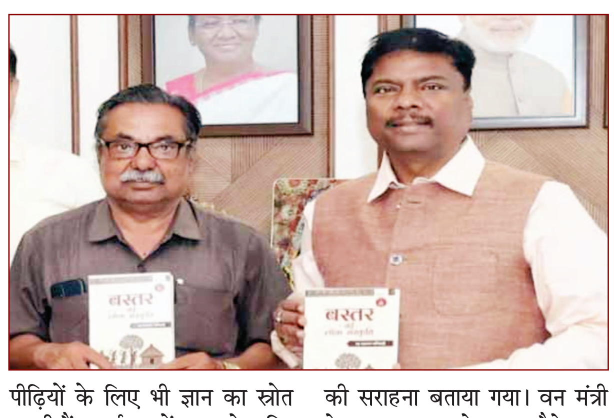

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, जनजातीय परंपराओं और साहित्यिक विरासत को नई पहचान देने वाली तीन पुस्तकों का विमोचन वन मंत्री केदार कश्यप ने आज सोमवार को किया। कार्यक्रम में साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में योगदान देने वाले लेखकों, साहित्यकारों का सम्मान भी हुआ। इस दौरान छत्तीसगढ़ी साहित्यकार डॉ. गीतेश अमरोहित सरस्वती बुक्स के प्रकाशक आकाश महेश्वरी मौजूद रहे।

केदार कश्यप ने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जनजातीय संस्कृति, लोक परंपराओं, ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण में लेखकों की भूमिका अहम है। उन्होंने कहा कि ऐसी पुस्तकें वर्तमान पीढ़ी को जड़ों से जोड़ती हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ज्ञान का स्रोत बनती हैं। कार्यक्रम में बस्तर के वरिष्ठ साहित्यकार रुद्रनारायण पाणिग्रही को धुरवा पटका भेंटकर साहित्य लेखन, लोक संस्कृति के संरक्षण में योगदान के लिए स्मृति-चिह्न प्रदान किया गया। इसे साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में उनके लंबे समय के काम की सराहना बताया गया। वन मंत्री केदार कश्यप ने इस मौके पर रुद्रनारायण पाणिग्रही की पुस्तक 'बस्तर की लोक संस्कृति' का विमोचन किया। पुस्तक में बस्तर की सांस्कृतिक परंपराओं, लोक मान्यताओं, रीति-रिवाजों, सामाजिक जीवन का विस्तृत वर्णन है। केदार कश्यप ने डॉ. संजय अलंग की पुस्तक 'छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प परंपरा एवं संस्कृति' का भी विमोचनकिया। डॉ. भागेश्वर पात्र की पुस्तक 'हल्बा जनजाति' भी जारी की गई। रुद्रनारायण पाणिग्रही ने कहा कि बस्तर की संस्कृति और परंपराओं को व्यापक स्तर पर पहुंचाना उनका उद्देश्य रहा है। मौजूद साहित्यकारों ने ऐसे आयोजनों को साहित्य, संस्कृति के संवर्धन के लिए जरूरी बताया। कार्यक्रम में साहित्य, संस्कृति, जनजातीय जीवन पर आधारित पुस्तकों की उपयोगिता पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि बस्तर और छत्तीसगढ़ की लोक परंपराओं को दस्तावेजी रूप देने का काम साहित्यकार लगातार कर रहे हैं। यह समाज और शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी है।

चार पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल का स्टॉक हुआ समाप्त

बीजापुर। जिला मुख्यालय बीजापुर में संचालित पेट्रोल पंपों में से चार पेट्रोल पंपों पर रविवार को ईंधन (पेट्रोल/डीजल) का स्टॉक अस्थायी रूप से समाप्त होने के कारण आज सोमवार को उनके संचालन में बाधा उत्पन्न हुई। इस संबंध में जानकारी प्राप्त होते ही जिला प्रशासन ने संबंधित पेट्रोल पंप संचालकों से संपर्क कर आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

जिला मुख्यालय में साप्ताहिक बाजार के दिन बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं आम नागरिक विभिन्न कार्यों से आते हैं, जिससे ईंधन की मांग में वृद्धि होती है। ऐसी स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सभी पेट्रोल पंप संचालकों को पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल एवं डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा समय पर ईंधन की आपूर्ति बनाए रखने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन की कमी की स्थिति उत्पन्न न हो तथा उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

जिन पेट्रोल पंपों पर ईंधन का स्टॉक समाप्त हुआ, उनमें पामभोई ऑटोमोबाइल्स बीजापुर, लुंकड़ फ्यूल्स बीजापुर, जीवीआर कोटपाल और जेएमवी फ्यूल्स नैमेड शामिल हैं। जिला प्रशासन द्वारा स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है एवं आवश्यकतानुसार समन्वय स्थापित कर ईंधन आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़, झोलाछाप डॉक्टरों पर नहीं हो रही कार्रवाई

बलरामपुर। जिले के रामानुजगंज सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में एक बार फिर झोलाछाप डॉक्टरों का जाल तेजी से फैलता नजर आ रहा है। महावीरगंज, विजयनगर, सनावल समेत कई गांवों में बिना मान्यता और बिना चिकित्सकीय योग्यता वाले लोग खुलेआम मरीजों का इलाज कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इन कथित डॉक्टरों का कारोबार वर्षों से जारी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से अब विभाग की कार्यप्रणाली और मंशा दोनों सवालों के घेरे में हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में झोलाछाप डॉक्टर मरीजों को तत्काल राहत देने के नाम पर हाई डोज एंटीबायोटिक, स्टेरॉयड और अन्य शक्तिशाली दवाइयां धड़ल्ले से दे रहे हैं। मरीजों को कुछ समय के लिए राहत तो मिल जाती है, लेकिन इसके गंभीर दुष्परिणाम बाद में सामने आते हैं। कई मामलों में गलत इलाज और लापरवाही के कारण मरीजों की जान तक चली गई है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से कोई ठोस पहल नजर नहीं आ रही है।

रामानुजगंज और आसपास के क्षेत्रों में कई मेडिकल स्टोर संचालकों ने अपनी दुकानों को ही क्लीनिक का रूप दे दिया है। कहीं इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं तो कहीं बेड लगाकर मरीजों को भर्ती तक किया जा रहा है। बिना किसी वैध अनुमति के इलाज का यह खेल खुलेआम चल रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खामोशी दिखाई देती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इन गतिविधियों की पूरी जानकारी है। शिकायतें भी कई बार की गईं, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से लोगों के बीच यह चर्चा आम है कि कहीं न कहीं इन झोलाछाप डॉक्टरों को विभागीय संरक्षण प्राप्त है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वालों पर हाथ डालने से जिम्मेदार अधिकारी बचते नजर आते हैं? लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार मिल रही शिकायतों के बावजूद विकासखंड चिकित्सा अधिकारी (बीएमओ) डॉ. महेश गुप्ता द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं किए जाने से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। सवाल यह है कि जब ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध क्लीनिक और झोलाछाप डॉक्टर खुलेआम मरीजों का इलाज कर रहे हैं तो स्वास्थ्य विभाग की टीम उन्हें रोकने में असफल क्यों है?

विभागीय बैठकों और सरकारी रिपोर्टों में अवैध चिकित्सा पर रोक लगाने के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि गांवों में मरीज आज भी अपात्र और अनुभवहीन लोगों के भरोसे इलाज कराने को मजबूर हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का फायदा उठाकर झोलाछाप डॉक्टर ग्रामीणों की मजबूरी को कमाई का जरिया बना रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि अनियंत्रित एंटीबायोटिक और गलत दवाओं का उपयोग न केवल मरीज की जान के लिए खतरा है, बल्कि भविष्य में दवा प्रतिरोधक क्षमता (एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस) जैसी गंभीर समस्या को भी जन्म दे सकता है। इस संबंध में आज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. विजय कुमार सिंह ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही बीएमओ को निर्देशित कर जांच एवं आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

बिलासपुर और बेंगलुरु के बीच स्पेशल समर ट्रेन चलाने का फैसला

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बिलासपुर और बेंगलुरु के बीच स्पेशल समर ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन बिलासपुर और बेंगलुरु छावनी के बीच एक फेरे के लिए संचालित की जाएगी।

रेलवे प्रबंधन से मिली जानकारी के मुताबिक, गाड़ी संख्या 08263 बिलासपुर-बेंगलुरु छावनी समर स्पेशल 12 जून (शुक्रवार) को बिलासपुर से रवाना होगी। यह ट्रेन एक तरफा (वन-वे) सेवा के रूप में संचालित की जाएगी। इस विशेष ट्रेन का ठहराव बिलासपुर, भाटापारा, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, डोंगरगढ़ और गोंदिया स्टेशनों पर होगा , जिससे छत्तीसगढ़ के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।

समर स्पेशल ट्रेन में कुल 18 कोच होंगे, जिनमें 2 एसएलआरडी, 6 सामान्य (जनरल) तथा 10 स्लीपर कोच शामिल हैं। इस व्यवस्था के कारण दक्षिण भारत की ओर यात्रा करने वालों को अतिरिक्त सीटें उपलब्ध हो सकेंगी। ट्रेन 12 जून को दोपहर 2 बजे बिलासपुर से रवाना होगी।इसके बाद यह भाटापारा, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, डोंगरगढ़ और गोंदिया होते हुए महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के विभिन्न प्रमुख स्टेशनों से गुजरते हुए दूसरे दिन रात 8 बजे बेंगलुरु छावनी स्टेशन पहुंचेगी।

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक : कैलाश नाथ द्वारा शिवम पब्लिकेशन एण्ड स्टेशनरीज इण्डस्ट्रीज-157प्रेस भवन,मधुबन विहार (ज्ञानेश्वर सोसायटी) ,वार्ड-85, होशंगाबाद रोड, भोपाल म.प्र.462047 से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक : सुशील कुमार त्रिपाठी , Mobile-91- 9893982060,
Email- mptmnp@gmail.com , website:tarunmitra.in , RNI : MPHIN/2021/79825 ; "इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के तहत उत्तरदायी। समस्त विवाद भोपाल न्यायालय के अधीन होंगे।

पुलिस भर्ती परीक्षा में नकल माफियाओं पर कड़ी नजर

- डीएम-एसपी ने परीक्षा केन्द्र की परखी सुरक्षा व्यवस्था
- सीसीटीवी, स्ट्रांग रूम व सुरक्षा इंतजामों की ली क्लास

फतेहपुर, 08 जून (तरुणमित्र)। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और नकलविहीन वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दिया। सोमवार को जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स एवं पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने परीक्षा केंद्रों पर अचानक पहुंचकर व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया, जिससे केंद्र व्यवस्थापकों में भी सतर्कता बढ़ गई।

डीएम और एसपी ने पॉलीटेक्निक कॉलेज एवं राजकीय इंटर कॉलेज का औचक निरीक्षण कर परीक्षा संचालन की पूरी व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों ने परीक्षा कक्षों, कंट्रोल रूम, सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था, स्ट्रांग रूम तथा सुरक्षा इंतजामों का बारीकी से परीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्रों पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि परीक्षा की शुचिता और गोपनीयता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। निरीक्षण के दौरान सीसीटीवी कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग, परीक्षार्थियों की सघन जांच, प्रवेश प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था को विशेष रूप से देखा गया। अधिकारियों ने यह भी सुनिश्चित किया कि परीक्षा केंद्रों पर शासन की गाइडलाइन का अक्षरशः पालन हो रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप भर्ती परीक्षा को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

वहीं पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को पूरी सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए। जनपद के सभी परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में आयोजित उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और नकलविहीन माहौल में संपन्न हुई। प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की लगातार निगरानी के चलते परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह सुचारु रही और कहीं से किसी प्रकार की अव्यवस्था की सूचना नहीं मिली।

खाकी के आंगन से निकले होनहारों का सम्मान, मेधावी बच्चों पर बरसे पुरस्कार

फतेहपुर, 08 जून (तरुणमित्र)। रिजर्व पुलिस लाइन में सोमवार को उस समय गौरव और उत्साह का केंद्र बन गई, जब वामा सारथी (उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन) के तत्वावधान में पुलिस परिवार के मेधावी छात्र-छात्राओं के सम्मान में भव्य समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वामा सारथी की जनपद अध्यक्ष कृति मांगलिक ने की। समारोह में शैक्षिक सत्र 2025-26 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करने वाले पुलिस कर्मियों के होनहार बेटों-बेटियों को प्रशस्ति-पत्र एवं पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे, वहीं अभिभावकों की आंखों में गर्व साफ दिखाई दिया। श्रीमती कृति मांगलिक ने कहा कि मेहनत, अनुशासन और लगन से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों को निरंतर आगे बढ़ने, शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करने तथा देश और समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया।

28 जून तक मत्स्य विभाग की योजनाओं के लिए करें आवेदन

कन्नौज, 08 जून (तरुणमित्र)। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, ने अवगत कराया है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में मत्स्य विभाग द्वारा संचालित राज्य सेक्टर की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए विभागीय पोर्टल http://fisheries.up.gov.in दिनांक 08 जून 2026 से 28 जून 2026 तक आवेदन हेतु खुला रहेगा।उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषादराज बोट सब्सिडी योजना तथा सघन मत्स्य पालन हेतु एरेशन सिस्टम स्थापना योजना के अंतर्गत इच्छुक लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक योजना हेतु पृथक-पृथक आवेदन करना अनिवार्य होगा।योजनाओं के अंतर्गत परियोजना का विस्तृत विवरण, इकाई लागत, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक अभिलेख एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी विभागीय वेबसाइट "http://fisheries.up.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदक आवेदन करने से पूर्व वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों का अवलोकन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजनाओं से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन की स्थिति में संशोधित प्रावधान लागू होंगे।

न्यायाधीश विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया जिला कारागार का निरीक्षण

कन्नौज, 08 जून (तरुणमित्र)। न्यायाधीश / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती अनुजा सिंह द्वारा जिला कारगार का निरीक्षण कर बंदियों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं सुनी। सचिव द्वारा किशोर, महिला व पुरूष बंदियों से अलग-अलग बातचीत की और उनकी आवश्यकताओं और समस्याओं को गम्भीरता से सुना। इस दौरान बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता, जमानत के प्रावधानों और न्यायिक प्रक्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। सचिव ने बंदियों को आश्वत किया कि विधिक सेवा प्राधिकरण उनके अधिकारों की रक्षा के लिये प्रतिबद्ध है। निरीक्षण के दौरान कारागार की व्यवस्थाओं, जिनमें खान-पान स्वास्थ्य सेवाये, स्वच्छता, शिक्षा और अन्य सुविधाओं शामिल है, का जेल मैनुअल के अनुरूप गहन परीक्षण किया गया।

बंदियों द्वारा किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं की गयी। निरीक्षण उपरांत अयोजित विधिक साक्षरता शिविर में बंदियों को निःशुल्क अधिवक्ता सुविधा, उनके कानूनी अधिकारों और न्याय प्राप्त करने की प्रकिया के बारे में विस्तार से समझाया गया तथा उन्होने ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर औज जरूरतमंद व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हर संभव विधिक सहायता प्रदान की जाती है तथा साथ ही साथ कुछ कोशिशे ग्रुप के सहयोग से कारागार में निरूद्ध बंदियों की जरूरत के तहत इस भीषण में कुछ कोशिशे ग्रुप द्वारा चप्पलें वितरितण कर सराहनीय कार्य किया उक्त कार्यक्रम में प्रभारी जेल अधीक्षक रविन्द्र नाथ, वार्डर दीपक, कुछ कोशिशे से सुनिल कुमार, अजय कुमार सहित अन्य सम्बन्धित जन भी उपस्थित है।

मुंडेरा में घरेलू हिंसा से संरक्षण के प्रति महिलाओं को किया जागरूक

हमीरपुर, 08 जून (तरुणमित्र)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमीरपुर की सचिव श्रीमती वन्दना अग्रवाल के कुशल दिशा निर्देशन में आज मुंडेरा पंचायत भवन में स्थित लीगल एड क्लीनिक में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ। पीएलवी गणेश सिंह ने घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम की जानकारी देते हुए महिलाओं को विधिक सहायता के प्रति जागरूक किया। पीएलवी गणेश सिंह ने घरेलू हिंसा के अंतर्गत शारीरिक हिंसा, यौन हिंसा, भावनात्मक हिंसा/मानसिक हिंसा, आर्थिक हिंसा, मौखिक हिंसा, सामाजिक हिंसा, उपेक्षा या उदासीनता बरतना के संबंध में जानकारी दी। पीएलवी गणेश सिंह ने घरेलू हिंसा अधिनियम की प्रमुख धाराओं के अतिरिक्त भारतीय न्याय संहिता की भी जानकारी दी।

एसपी ने गुप्त जांच के बाद दो उपनिरीक्षकों को सौंपी थानों की कमान

- लापरवाही पर आईजी ने दो थानेदारों सहित चौकी प्रभारी को किया था निलंबित
- किशनपुर थाने में योगेश कुमार व खखरेरू थाने में सतपाल सिंह को बनाया प्रभारी

विजयीपुर ,फतेहपुर, 08 जून (तरुणमित्र)। जनपद की पुलिस व्यवस्था में जवाबदेही और अनुशासन कायम करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने गुप्त जांच के बाद रिक्त पड़े दो थानों की कमान नए उपनिरीक्षकों को सौंप दी है। रविवार को शासन की मंशा के अनुरूप प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। जनपद के तेजतर्रार एवं ईमानदार पुलिस अधीक्षक ने गहन जांच और प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर अपराध शाखा में तैनात उपनिरीक्षक योगेश कुमार को किशनपुर थाने की कमान सौंपी, जबकि पुलिस लाइन में तैनात उपनिरीक्षक सतपाल सिंह को खखरेरू थाने का नया प्रभारी बनाया गया है।दोनों थानों को लेकर लंबे समय से अपराध नियंत्रण में विफलता, अनुशासनहीनता, शिथिलता, अनैतिक गतिविधियों तथा कानून-व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण न होने संबंधी शिकायतें लगातार मुख्यालय तक पहुंच रही थीं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रयागराज परिक्षेत्र के अपर पुलिस महानिदेशक ज्योति नारायण तथा पुलिस महानिरीक्षक ने पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया और संबंधित मामलों की समीक्षा कराई।

खखरेरू थाना क्षेत्र में बढ़ते अपराध, चोरी की घटनाओं के खुलासे में असफलता एवं क्षेत्र के पौली गांव में बीते सप्ताह आयोजित उर्स के दौरान आयोजकों से अभद्रता पूर्वक व्यवहार करना तथा कानून-व्यवस्था पर प्रभावी अंकुश न लग पाने को लेकर लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। वहीं किशनपुर थाना क्षेत्र में भी अवैध गतिविधियों और गंभीर मामलों में अपेक्षित कार्रवाई न किए जाने को लेकर उच्चाधिकारियों तक शिकायतें पहुंच रही थीं। बीते माह हुई लूट और छीना-झपटी की घटना में शांति भंग की कार्रवाई के माध्यम से आरोपियों को राहत दिए जाने की शिकायतों ने भी अधिकारियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। बीते सप्ताह खखरेरू और किशनपुर थाना क्षेत्र के मध्य सधुवापुर के पास बोलेरो एवं बाइक सवार बदमाशों द्वारा एक पशु व्यापारी से तीन लाख रुपये की लूट की घटना ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को मिलने के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई न होने तथा मामले को गंभीरता से न लेने की चचाएं सामने आईं।

अधिकारियों की घोर लापरवाही : श्मशान, खलिहान की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे

हमीरपुर, 08 जून (तरुणमित्र)। विकासखंड मौदहा क्षेत्र के ग्राम लेवा की प्रशासक ग्राम प्रधान बृजरानी ने जिलाधिकारी हमीरपुर को पत्र भेजकर मरघट और खलिहान की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का आरोप लगाया है। प्रधान ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने जमीन कब्जा मुक्त नहीं कराई तो वह बच्चों को लेकर दिल्ली मजदूरी करने चली जाएंगी। बृजरानी पत्नी स्वर्गीय संतोष कुमार वर्मा ने पत्र में बताया कि ग्राम सभा की मरघट व खलिहान की जमीन पर राजेश वर्मा, रामप्रसाद प्रजापति, दिनेश सिंह, अनिल सिंह चौहान एवं चंद्रभान सिंह ने अस्थाई कब्जा कर लिया है। वहीं बच्चू यादव व सुरेंद्र सिंह ने कच्चा घर बनाकर स्थाई कब्जा कर लिया है। ग्राम निधि से मरघट गाटा संख्या 365 की चौहद्दी एंगल-जाली लगवाई जा रही थी और हैंडपंप बोरिंग का कार्य चल रहा था। तभी राजेश वर्मा ने खुद का कब्जा बताकर काम रुकवा दिया। आरोप है कि राजेश वर्मा आए दिन सरकारी काम में बाधा डालता है और पत्नी को आगे कर गाली-गलौज व जान-माल की धमकी देता है।

प्रधान ने लेखपाल पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि लेखपाल ने गौशाला की सरकारी लकड़ी मिलीभगत कर बिकवा दी। सरकारी कर्मचारी हरिजन एक्ट में फंसाने के डर से कार्यवाही नहीं करते, क्योंकि राजेश वर्मा पहले भी कई लोगों पर मुकदमा लगा चुका है। प्रशासक/,प्रधान बृजरानी ने डी एम से गाटा संख्या 365 मरघट व गाटा संख्या 306 खलिहान पर राजस्व टीम गठित कर जांच कराने और कब्जा मुक्त कराने की मांग की है, ताकि तार फेंसिंग व वृक्षारोपण का कार्य कराया जा सके। साथ ही हैंडपंप का रुका कार्य दोबारा शुरू हो सके। यदि जिलाधिकारी द्वारा अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो मैं मजबूर होकर गांव का काम छोड़कर दिल्ली में मजदूरी करने के बच्चों के साथ चली जाऊंगी ।

विद्युत समस्या : उपखण्ड कार्यालय में किसानों ने धरना देकर विद्युत आपूर्ति बहाल करने की उठाई मांग

सुमेरपुर ,हमीरपुर , 08 जून (तरुणमित्र)। पिछले माह आए तूफान से ध्वस्त हुई विद्युत लाइनों के कारण नलकूप ठप होने से किसान धान की नर्सरी नहीं तैयार कर पा रहे हैं। नलकूपों की आपूर्ति बहाल करने की मांग को लेकर टेढ़ा के किसानों ने गांव स्थित सब स्टेशन में धरना देकर नलकूपों की आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। किसानों का कहना कि धान की नर्सरी को प्रत्येक दशा में 15 जून तक बो जानी चाहिए। गत माह 28 मई की रात आए भयानक तूफान में सर्वाधिक कहर सुमेरपुर क्षेत्र में बरपाया था। तूफान के चलते सुमेरपुर डिविजन में 1703 पोल क्षतिग्रस्त हुए थे। विद्युत विभाग अभी तक 50 फीसदी पोल नहीं लगा सका है। तूफान के बाद से नलकूपों की आपूर्ति अभी तक बहाल नहीं हो सकी है। रविवार को टेढ़ा के किसान जगमोहन, अभिषेक, वीरेंद्र सिंह, मनीष सिंह,महेश तिवारी, दीपू तिवारी, चंचल सिंह, पंकज यादव,टिल्ला सिंह, मुलायम सिंह, सुरेश सिंह, राकेश गुप्ता, जितेंद्र सिंह, सुखराम यादव, राजेश कुशवाहा, महेश मिश्रा, मुन्नू तिवारी आदि ने टेढ़ा विद्युत सब स्टेशन में धरना देकर नलकूपों की आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। किसानों ने बताया कि गांव में करीब 500 से अधिक निजी नलकूप लगे हुए हैं। इनमें करीब 450 नलकूप मौजूदा समय में ठप हैं।

भैंसापाली गांव में हुई नाला एवं तालाब सफाई

हमीरपुर, 08 जून (तरुणमित्र)। विकासखंड कुरारा के ग्राम भैंसापाली में नाला सफाई एवं तालाबों की दुर्दशा की शिकायत पर जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने संज्ञान लेते हुए जिला पंचायत राज्य अधिकारी को निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी को ग्रामीणों ने बताया कि गांव में लगभग 10 वर्षों से नालों की समुचित सफाई नहीं हुई , जिसके कारण बरसात के दौरान कुशवाहा बस्ती एवं अहिरवार बस्ती में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। कई कच्चे मकानों को नुकसान और क्षतिग्रस्त हुए थे। गांव के तालाबों में जलकुंभी (पन चिरई) फैल जाने एवं सफाई न होने से तालाब के पानी का उपयोग नहीं हो पाता है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला पंचायत राज अधिकारी श्रीमती सुबोध जोशी आज ग्राम भैंसापाली में विशेष सफाई अभियान चलाकर नालों की सफाई एवं तालाबों से जलकुंभी हटाई गई। उन्होंने अधिकारियों को नियमित रूप से साफ सफाई बनाए रखने तथा बरसात के मौसम में जलभराव की समस्या न होने देने के निर्देश दिए गए हैं।

राजघाट बांध की मत्स्य आखेट नीलामी में अनियमितता का आरोप,जिलाधिकारी से जांच की मांग

ललितपुर, 08 जून (तरुणमित्र)। राजघाट बांध के डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में मत्स्य आखेट (मछली पकड़े) की नीलामी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय मछुआरों एवं छोटे ठेकेदारों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर वर्ष 2026-27 की नीलामी प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि वर्ष 1999 से राजघाट बांध के डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में मत्स्य आखेट की नीलामी प्रतिवर्ष विधिवत विज्ञप्ति जारी कर कराई जाती रही है। आरोप है कि वर्ष 2026-27 के लिए अब तक कोई सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है, जबकि संबंधित क्षेत्र को कथित रूप से बिना नीलामी के ही शामिल कर लिया गया है। शिकायतकताओं का कहना है कि इस प्रक्रिया में बेतवा रिवर बोर्ड के अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत होने की आशंका है। उनका आरोप है कि बिना पारदर्शी नीलामी के कार्य आवंटित किए जाने से छोटे ठेकेदारों और मछुआरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। इससे उनके परिवारों के भरण-पोषण तथा बच्चों की शिक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए तथा नियमों के अनुसार सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी कर नीलामी प्रक्रिया संपन्न कराई जाए। ज्ञापन पर मोहसिन खान, मोनू राजा, विनय विश्वकर्मा आदि के हस्ताक्षर हैं।

मुख्य मांगें

मत्स्य आखेट नीलामी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच। कथित अनियमितताओं की कानूनी जांच एवं कार्रवाई। सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी कर नियमानुसार नीलामी कराई जाए। छोटे ठेकेदारों एवं मछुआरों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए।

केमिकल से पकाए जा रहे आम, लोगों की सेहत पर मंडरा रहा खतरा

ललितपुर, 08 जून (तरुणमित्र)। गर्मी के मौसम में आम की बढ़ती मांग के बीच बाजार में केमिकल से पकाए गए आमों की बिक्री धड़ल्ले से होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। जानकारों के अनुसार कई व्यापारियों द्वारा कच्चे आमों को कृत्रिम रूप से जल्दी पकाने के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं की सेहत पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। बताया जाता है कि आम की प्रत्येक क्रेट के साथ चार से छह केमिकल पाउच दिए जा रहे हैं। इन रसायनों के प्रभाव से कच्चे आम कुछ ही घंटों में पीले होकर पके हुए दिखाई देने लगते हैं। हालांकि बाहरी रूप से आकर्षक दिखने वाले ये फल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि केमिकल से पकाए गए फलों के लगातार सेवन से पेट संबंधी समस्याएं, एलर्जी, उल्टी, दस्त, सिरदर्द तथा अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इसके बावजूद बाजार में ऐसे आमों की बिक्री खुलेआम जारी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खाद्य सामग्री, फल-फ्रूट तथा फलों के रस की दुकानों पर नियमित जांच नहीं हो रही है। लोगों का कहना है कि मानव स्वास्थ्य से जुड़े इस गंभीर विषय पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को विशेष अभियान चलाकर जांच करनी चाहिए, ताकि मिलावटी और केमिकलयुक्त फलों की बिक्री पर रोक लगाई जा सके। नागरिकों ने मांग की है कि बाजार में बिक रहे आमों और अन्य फलों के नमूने लेकर उनकी जांच कराई जाए तथा दोषी पाए जाने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

साथ ही लोगों को भी जागरूक किया जाए कि वह प्राकृतिक रूप से पके हुए फलों की पहचान कर सकें और अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकें।

जनता का सवाल

बाजार में रोजाना बिक रही खाद्य सामग्री, फल-फ्रूट और फलों के रस की गुणवत्ता की निगरानी किस प्रकार की जा रही है? यदि केमिकलयुक्त फलों की बिक्री हो रही है तो संबंधित विभाग की ओर से प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं दिखाई दे रही? यह सवाल आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

रोजगार मांग रही वाल्मीकि समाज की महिलाओं ने किया प्रदर्शन

ललितपुर, 08 जून (तरुणमित्र)। बाल्मीकि समाज की बेरोजगार महिलाओं ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर नगर पालिका परिषद ललितपुर में तैनात एक संविदा सफाई कर्मचारी एवं कार्यवाहक स्वास्थ्य नायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि रोजगार की मांग को लेकर चलाए जा रहे उनके अभियान को बदनाम करने और प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर कठोर कार्रवाई की मांग की गई है।

शिकायती पत्र में कहा गया है कि वाल्मीकि समाज की कई बेरोजगार महिलाएं लंबे समय से नगर पालिका और जिला प्रशासन से रोजगार उपलब्ध कराने की मांग कर रही हैं। महिलाओं का आरोप है कि उनके द्वारा दिए गए ज्ञापनों और रोजगार संबंधी मांगों को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है तथा उन पर और उनके समर्थकों पर निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। महिलाओं ने बताया कि 24 मई 2026 को नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी को तथा बाद में जिलाधिकारी और मंडलायुक्त झांसी को भी ज्ञापन सौंपा गया था। आरोप है कि इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके आंदोलन को कमजोर करने और भ्रम फैलाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां और आरोप लगाए गए। शिकायतकताओं ने कहा कि यदि किसी महिला से किसी प्रकार की अवैध वसूली की गई होती तो वह स्वयं इसकी शिकायत करती। महिलाओं का कहना है कि रोजगार की मांग को लेकर चल रहे अभियान को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं।

ज्ञापन में संबंधित कर्मचारी पर अपने पद का दुरुपयोग करने, मनमाने तरीके से कर्मचारियों को हटाने और अपने परिजनों को लाभ पहुंचाने जैसे आरोप भी लगाए गए हैं। महिलाओं ने दावा किया कि पूर्व में भी इस संबंध में नगर पालिका प्रशासन को शिकायतें दी गई थीं, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि संबंधित कर्मचारी द्वारा उपस्थिति रजिस्टर और स्थानांतरण प्रक्रिया में अनियमितताएं की गईं। महिलाओं का कहना है कि कई मामलों में शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने से संबंधित कर्मचारी के हौसले बढ़ गए हैं। महिलाओं ने जिलाधिकारी से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कठोर विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रदर्शन के दौरान आरती, पूनम, सपना, सीमा, राधा, किरन, नीतू, संजना, काजल, करनजीत, प्रीति, काजल, ज्योति, किरन, अरूना, सुषमा, नविता, रंजना, नविता, सरोज, शीतल, नीतू, आरती, वंदना, आरती, अनीता, नेहा, वर्षा, प्रभा, रेखा, पूजा, नेहा, नीतू, काजल, हेमा, कंचन, भारती, रंजीता, आरती, कल्पना, सपना, सरोज, नेहा, अमिता सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

पुलिस भर्ती परीक्षा केन्द्रों का डीआईजी व आयुक्त ने लिया जायजा

बांदा, 08 जून (तरुणमित्र)। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा 08, 09 एवं 10 जून 2026 को आयोजित है। परीक्षा को सकुशल, निष्पक्ष, नकलविहीन एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने हेतु चित्रकूटधाम परिक्षेत्र के जनपदों में व्यापक सुरक्षा एवं निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, चित्रकूटधाम परिक्षेत्र, बांदा व आयुक्त चित्रकूटधाम मण्डल बांदा द्वारा आज पं0 जे.एन.पी.जी कॉलेज व नगर पालिका बालिका उ0मा0 विद्यालय जनपद बांदा के परीक्षा केन्द्रों का भ्रमण कर परीक्षा की तैयारियों एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केन्द्रों पर अभ्यर्थियों के प्रवेश एवं निकास व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी, कंट्रोल रूम संचालन, प्रश्नपत्रों की सुरक्षा, पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती तथा यातायात प्रबंधन सहित सभी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

परीक्षा की शुचिता एवं पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जोनल एवं सेक्टर स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। सभी परीक्षा केन्द्रों पर सतत निगरानी रखी जाएगी तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता, नकल अथवा अनुचित साधनों के प्रयोग के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा निर्देशित किया गया है कि परीक्षा केन्द्रों पर आने वाले अभ्यर्थियों की सघन चेकिंग की जाए तथा प्रतिबंधित एवं इलेक्ट्रानिक उपकरणों को परीक्षा केन्द्रों में ले जाने से पूर्णतः रोका जाए। साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों एवं गतिविधियों पर विशेष नजर रखते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखी जाए। चित्रकूटधाम परिक्षेत्र पुलिस परीक्षा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित, निष्पक्ष एवं नकलविहीन वातावरण में संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है ।

मामूली विवाद में माँ की हत्या करने वाला पुत्र गिरफ्तार

बांदा, 08 जून (तरुणमित्र)। जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मामूली विवाद में अपनी माँ की हत्या करने वाले पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है ।गौरतलब हो कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम गुरेह के रहने वाले पप्पू उर्फ राधाचरन पुत्र मुनुवा ने कल सायंकाल मामूली विवाद में अपनी माँ को पक्के रास्ते पर उठाकर पटक दिया और सिर में गम्भीर चोटें आने के कारण उनकी मृत्यु हो गई । प्रकरण में मृतका के बेटे की तहरीर पर थाना कोतवाली देहात में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया ।जिसे आज नियमानुसार न्यायालय भेजा गया।

डीएम व एसपी ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का किया औचक निरीक्षण

चित्रकूट, 08 जून (तरुणमित्र)। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा-2025 को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी पुलकित गर्ग एवं पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह द्वारा जनपद के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

प्रशासनिक अधिकारियों के इस संयुक्त दल ने जनपद में संचालित छह केंद्रों में से मुख्य रूप से निम्नलिखित परीक्षा केंद्रों का सघन निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया जिसमे चित्रकूट इंटर कॉलेज चित्रकूट, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, कर्वी, श्री गंगा प्रसाद जनसेवा इंटर कॉलेज, कर्वी, सेठ राधा कृष्ण पोद्दार इंटर कॉलेज, सीतापुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने चित्रकूट इंटर कॉलेज में अभ्यर्थियों के फेशियल रिकग्निशन (चेहरा प्रमाणीकरण) और डिजिटल स्कैनिंग का कार्य कर रही अधिकृत एजेंसी 'इनोवेटिव वोटिंग व्यू' के तकनीकी सुपरवाइजर से स्कैनिंग प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा व्यावहारिक रूप से उसका सत्यापन भी देखा।

तकनीकी मानकीकरण के संबंध में पूछने पर सुपरवाइजर द्वारा अवगत कराया गया कि स्थापित नियमों के अनुसार, यदि अभ्यर्थी का न्यूनतम 50 प्रतिशत तक फेस मिलान (चेहरा मिलान) हो जाता है, तो उसे प्रामाणिक एवं मान्य श्रेणी में स्वीकार किया जाता है।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी श्री पुलकित गर्ग ने परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों के लिए बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रीष्मकाल को देखते हुए केंद्रों पर स्वच्छ एवं ढके हुए पेयजल की समुचित व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए।

कलेक्टर प्रतिभा पाल की सख्ती: सिविल सर्जन और करारपुर सीएमओ का वेतन रोका

सागर। मध्य प्रदेश के सागर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन और जनसमस्याओं के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समय-सीमा (टीएल) बैठक में विभिन्न विभागों की समीक्षा के दौरान उन्होंने कई अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में स्वास्थ्य विभाग और नगरीय प्रशासन से जुड़े कार्यों की समीक्षा के दौरान गंभीर कमियां सामने आईं। बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद समय-सीमा बैठक में अनुपस्थित रहने तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की गतिविधियों में संतोषजनक प्रगति नहीं मिलने पर कलेक्टर ने सागर के सिविल सर्जन का वेतन आगामी आदेश तक रोकने के निर्देश दिए। वहीं, विभागीय कार्यों में लापरवाही और लंबित प्रकरणों के निराकरण में उदासीनता पाए जाने पर करारपुर के मुख्य नगरपालिका

अधिकारी (सीएमओ) का वेतन भी तत्काल प्रभाव से रोकने के आदेश जारी किए गए।राजस्व प्रकरणों की समीक्षा के दौरान नामांतरण और सीमांकन के कई मामले लंबे समय से लंबित पाए गए। इस पर कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए तीन से छह माह से लंबित नामांतरण प्रकरणों वाले संबंधित तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

सीमांकन मामलों को लेकर उन्होंने राजस्व निरीक्षकों और पटवारियों को फील्ड स्तर पर कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि 20 जून तक सीमांकन से जुड़े सभी लंबित मामलों का निराकरण सुनिश्चित किया जाए।बैठक में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की भी समीक्षा की गई। जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को तीन दिनों के भीतर संबल योजना के लंबित पंजीयन पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सामान्य मृत्यु पर दो लाख रुपये और दुर्घटना मृत्यु पर चार लाख रुपये की अनुग्रह सहायता राशि सात दिन के भीतर हितग्राहियों को उपलब्ध कराने को कहा गया।कलेक्टर ने 50 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों के शत-प्रतिशत निराकरण पर विशेष जोर देते हुए अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा श्रमयोगी मानधन योजना, जल गंगा संवर्धन अभियान तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा कर प्रगति में तेजी लाने को कहा।उन्होंने जनसुनवाई, सीएम मॉनिटरिंग और विभिन्न आयोगों से प्राप्त प्रकरणों के प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ विवेक केवी, नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री, अपर कलेक्टर अविनाश रावत, सिटी मजिस्ट्रेट गगन बिसेन सहित जिले के सभी एसडीएम और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

महू-नीमच फोरलेन पर स्क्रैप से भरा लोडिंग वाहन पलटा

मंदसौर। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के फतेहगढ़ क्षेत्र में महू-नीमच फोरलेन हाईवे पर सोमवार को एक लोडिंग वाहन हादसे का शिकार हो गया। स्क्रैप सामग्री से भरा वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे में चालक को मामूली चोटें आई हैं, जबकि कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार, वाहन क्रमांक एमपी 3 जीए 3596 दलौदा से स्क्रैप सामग्री लेकर फतेहगढ़ स्थित टीएमटी फैक्ट्री की ओर जा रहा था। वाहन निर्धारित मार्ग से गुजर रहा था, तभी रास्ते में अचानक चालक का वाहन से नियंत्रण बिगड़ गया। प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार चालक वाहन को संभाल नहीं सका और लोडिंग वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। वाहन में भारी मात्रा में स्क्रैप सामग्री भरी हुई थी। हादसे के बाद सड़क पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई।

मरीजों को ले जाने वाली 108 एंबुलेंस बिमार, निजी वाहनों से अस्पताल पहुंचने को मजबूर मरीज

शहडोल। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के ब्यौहारी क्षेत्र स्थित निपानिया में संचालित 108 एंबुलेंस खराब हो गई है। इसके कारण ग्रामीण मरीजों और उनके परिजनों को अस्पताल पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह आपातकालीन एंबुलेंस पिछले कई दिनों से बंद है, जिससे क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं।स्थानीय निवासियों के अनुसार, खराब एंबुलेंस ब्यौहारी स्थित एक पेट्रोल पंप परिसर में खड़ी है। तकनीकी खराबी के कारण इसका संचालन ठप है और अब तक इसे ठीक कर सेवा में बहाल नहीं किया जा सका है। इस स्थिति के चलते दुर्घटना, प्रसव पीड़ा या अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में कठिनाई हो रही है।

ग्रामीणों ने बताया कि 108 एंबुलेंस सेवा दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। निपानिया और आसपास के गांवों में रहने वाले अधिकांश लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके लिए निजी वाहन की व्यवस्था करना मुश्किल होता है। एंबुलेंस बंद होने के कारण मरीजों को निजी वाहनों, ऑटो या अन्य साधनों से अस्पताल जाना पड़ रहा है, जिससे उन्हें अतिरिक्त समय और धन खर्च करना पड़ रहा है।क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया है कि जिले में संचालित कई 108 एंबुलेंसें अक्सर तकनीकी खराबी का शिकार होती रहती हैं। उनका कहना है कि नियमित रखरखाव और समय पर मरम्मत न होने के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। लोगों ने सुझाव दिया कि आपातकालीन वाहनों की नियमित जांच और तत्काल मरम्मत सुनिश्चित की जाए ताकि ऐसी समस्याओं से बचा जा सके। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि निपानिया की खराब 108 एंबुलेंस को तत्काल ठीक कर पुनः सेवा में लगाया जाए।

स्मार्ट मीटर व बढ़े बिजली बिलों के खिलाफ ग्रामीणों का हल्ला बोल, बिजली कंपनी कार्यालय का घेराव

हरदा। मध्य प्रदेश के हरदा जिले की सिराली तहसील में सोमवार को स्मार्ट मीटर, बढ़े हुए बिजली बिलों और बार-बार हो रही बिजली कटौती के विरोध में ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एकजुट होकर बिजली वितरण कंपनी के कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्र के जूनियर इंजीनियर (जेई) को हटाने की मांग भी उठाई। ग्रामीणों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद से बिजली बिलों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।

उनका कहना है कि पहले जहां सामान्य बिल आते थे, वहीं अब कई गुना अधिक राशि के बिल थमाए जा रहे हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर व्यवस्था का विरोध करते हुए कहा कि यह प्रणाली आम लोगों के हित में नहीं है। उनका कहना है कि प्रीपेड मीटर के कारण रिचार्ज समाप्त होते ही बिजली आपूर्ति बंद होने का खतरा बना रहता है, जिससे उपभोक्ताओं में असुरक्षा की भावना है।फुटकर व्यापारी संघ के जिलाध्यक्ष शेख असलम ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं के बिजली बिल लगातार बढ़ रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्रीय जेई योगेश गौर उपभोक्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेते, इसलिए उन्हें तत्काल यहां से हटाया जाना चाहिए। स्थिति की जानकारी मिलते ही प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से चर्चा की। अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि उनकी शिकायतें और मांगें बिजली कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाई जाएंगी।

ब्लड बैंक में रक्त संकट गहराया, दुर्लभ ब्लड ग्रुप की कमी बनी बड़ी चुनौती

दमोह। मध्य प्रदेश के दमोह जिला अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में इन दिनों रक्त की सीमित उपलब्धता स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। अस्पताल में प्रतिदिन दुर्घटना पीड़ितों, गंभीर मरीजों, प्रसूता महिलाओं तथा थैलेसीमिया और एनीमिया से पीड़ित रोगियों के लिए रक्त की जरूरत पड़ती है, लेकिन मांग के अनुरूप रक्त संग्रह नहीं हो पा रहा है। इसके चलते कई बार मरीजों के परिजनों को स्वयं रक्तदाताओं की तलाश करनी पड़ रही है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, सामान्य दिनों में भी ब्लड बैंक पर लगातार दबाव बना रहता है।

खासकर दुर्लभ रक्त समूहों की उपलब्धता बड़ी चुनौती बन गई है। आपातकालीन परिस्थितियों में ऐसे रक्त समूहों के दाताओं की व्यवस्था करना कई बार मुश्किल हो जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि एबी नेगेटिव, ओ नेगेटिव सहित अन्य दुर्लभ रक्त समूहों वाले दाताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। ऐसे में गंभीर मरीजों के इलाज के दौरान इन रक्त समूहों की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यही वजह है कि रक्तदान शिविरों में सभी आयु वर्ग और समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी को आवश्यक माना जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग समय-समय पर रक्तदान शिविर आयोजित कर लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित कर रहा है। हाल ही में आयोजित शिविरों के माध्यम से रक्त संग्रह किया गया, लेकिन अस्पताल की नियमित जरूरतों को देखते हुए अधिक जनभागीदारी की आवश्यकता महसूस की जा रही है। शहर के कई सामाजिक संगठन, युवा समूह और स्वयंसेवी संस्थाएं भी जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्तदाताओं की व्यवस्था करने में सहयोग कर रही हैं। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से रक्तदाताओं तक सूचना पहुंचाकर मरीजों की मदद की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने जिले में अधिक संख्या में रक्तदान शिविर आयोजित करने की योजना बनाई है। अधिकारियों का कहना है कि सामाजिक संगठनों और युवाओं के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि ब्लड बैंक में पर्याप्त रक्त भंडारण सुनिश्चित किया जा सके।

जिला अस्पताल दमोह के प्रभारी ब्लड बैंक डॉ. प्रशांत सोनी ने बताया कि अस्पताल में प्रतिदिन विभिन्न मरीजों के लिए रक्त की आवश्यकता रहती है। रक्तदान शिविरों के माध्यम से संग्रह बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से नियमित और स्वैच्छिक रक्तदान करने की अपील करते हुए कहा कि एक यूनिट रक्त किसी व्यक्ति की जान बचा सकता है।

नामांतरण के लिए 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथ गिरफ्तार

धार। मध्य प्रदेश के धार जिले के मनावर क्षेत्र में लोकायुक्त पुलिस ने सोमवार को भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को नामांतरण प्रकरण में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपित पटवारी आवेदक से नामांतरण की प्रक्रिया पूरी करने के बदले 20 हजार रुपये की मांग कर रहा था।

लोकायुक्त के कार्यवाहक निरीक्षक सचिन पटेरिया के अनुसार, ग्राम पंचायत कपस्थली निवासी अरुण कुमार तिवारी ने अपने दो प्लॉट अंकुश सोनी को बेचे थे।

इन प्लॉटों के नामांतरण की कार्रवाई के लिए संबंधित पटवारी प्रवीण पाटीदार ने प्रति प्लॉट 10 हजार रुपये के हिसाब से कुल 20 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। रिश्वत की मांग से परेशान होकर अरुण कुमार तिवारी ने लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में पुलिस अधीक्षक राजेश सहाय से शिकायत की। शिकायत के सत्यापन के दौरान आरोप सही पाए जाने पर लोकायुक्त टीम ने जाल बिछाया। योजना के तहत सोमवार को ग्राम डोचा स्थित तहसील कार्यालय में संचालित पटवारी कार्यालय में आरोपित प्रवीण पाटीदार को शिकायतकर्ता से 10 हजार रुपये की पहली किस्त लेते समय रंगे हाथों पकड़ लिया गया। लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2018 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

महा-जनसंपर्क अभियान के तहत सांसद गुप्ता एवं सांसद गुर्जर ने विभिन्न मंडलों में किया जनसंपर्क

मंदसौर। मध्य प्रदेश क मंदसौर जिले के विभिन्न भाजपा संगठनात्मक मण्डलों एवं शक्ति केंद्रो पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के 12 वर्षीय सेवा एवं समर्पण को समर्पित कार्यकाल को लेकर विभिन्न रचनात्मक एवं संगठनात्मक कार्य चल रहे हैं।इसी क्रम में सोमवार को महा-जनसंपर्क अभियान अन्तर्गत लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता एवं राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर ने जिले के विभिन्न मंडलों एवं शक्ति केंद्रों में संगठनात्मक प्रवास पर पहुंचे और कार्यकताओं एवं आमजन से संवाद किया, एक पेड मॉं के नाम अभियान अन्तर्गत पौधारोपण तथा केंद्र और राज्य सरकार कि योजनाओं के लाभार्थी हितग्राहियों का सम्मान किया।

जिला भाजपा द्वारा जिले में चलाए जाने वाले जन सर्म्पक अभियान हेतु भाजपा जिला महामंत्री शिवराजसिंह राणा, भाजपा जिला उपाध्यक्षगण जीवन शर्मा, सुनिल जैन, जितेन्द्रसिंह चौहान, गौरव अग्रवाल एवं भाजपा जिला मंत्री रामसिंह चौहान प्रभारी बनाये गये हैं। प्रवास के द्वितीय दिवस सांसद सुधीर गुप्ता ने सीतामऊ ग्रामीण मंडल के काचरिया-चिकला पंचायत एवं खेताखेड़ा, बसई मंडल के बसई एवं कुरावन, मेलखेड़ा मंडल के लसुडिया तथा खड़ावदा मंडल के बालोदा एवं बरखेड़ा गंगासा शक्ति केंद्रों का दौरा किया।

इसके पश्चात उन्होंने भानपुरा स्थित दुधाखेड़ी माताजी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता कर कार्यकताओं से संवाद किया तथा संगठन को और अधिक सशक्त बनाने का आह्वान किया।

भाई ही निकला भाई का कातिल, जमीन विवाद में रची हत्या की साजिश

4 दिन में भांडेर पुलिस ने किया ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार, पांच फरार

दतिया। मध्य प्रदेश के दतिया जिले भांडेर पुलिस ने जमीन और पारिवारिक संपत्ति के विवाद में हुई एक सनसनीखेज हत्या का चार दिनों में खुलासा कर दिया है। मामले का खुलासा सोमवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दतिया एएसपी सुनील कुमार शिवहरे एवं एसडीओपी भांडेर पूनमचंद यादव ने किया। एएसपी सुनील कुमार शिवहरे ने बताया कि 02 जून 2026 को ग्राम अजीतपुरा के समीप नदी में एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर आवश्यक कार्रवाई की। मृतक की पहचान विनोद यादव उर्फ खुशी यादव (38) निवासी अजीतपुरा के रूप में हुई। 03 जून को

मृतक के बड़े भाई मनोज यादव ने मर्ग कायम कराते हुए बताया था कि विनोद यादव दूध देने के लिए भाण्डेर गया था और वापस नहीं लौटा।

बाद में उसकी मोटरसाइकिल खेत में खड़ी मिली तथा नदी में उसका शव बरामद हुआ। प्रारंभिक तौर पर मामला दुर्घटना प्रतीत हो रहा था, लेकिन पुलिस को घटनाक्रम संदिग्ध लगा।

एसडीओपी पूनमचंद यादव ने बताया कि तकनीकी साक्ष्यों, वैज्ञानिक जांच एवं गहन पूछताछ के आधार पर मामले की सूक्ष्म विवेचना की गई। जांच के दौरान सामने आया कि मृतक का अपने परिजनों से जमीन और पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था।

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि मृतक के बड़े भाई मनोज यादव ने अपने साथियों करण यादव, राहुल यादव, रवि यादव, गुलशन यादव एवं आकाश दोहरे के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। आरोपियों ने विनोद यादव को कार में बैठाकर घुमाया, शराब पिलाई और अत्यधिक नशे की हालत में नदी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद घटना को दुर्घटनावश डूबने से हुई मौत साबित करने का प्रयास किया गया।साक्ष्यों के आधार पर थाना भांडेर में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस ने 08 जून को मुख्य आरोपी मनोज यादव को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उसे न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया है।पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। मामले में शामिल पांच आरोपी राहुल यादव, करण यादव, रवि यादव, गुलशन यादव एवं आकाश दोहरे अभी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।

एएसपी सुनील कुमार शिवहरे ने कहा कि फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस अंधे कत्ल का खुलासा करने वाली पुलिस टीम की सराहना करते हुए कहा कि तकनीकी एवं वैज्ञानिक जांच के माध्यम से कम समय में मामले का सफल खुलासा किया गया है।

टोल प्लाजा कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, सड़क किनारे मिला शव

आगरमालवा। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के सुसनेर-जीरापुर मार्ग स्थित एक टोल प्लाजा पर कार्यरत कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कर्मचारी का शव टोल प्लाजा के समीप सड़क किनारे मिलने से क्षेत्र में दहशत फैल गई।प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान धर्मेंद्र, निवासी ग्राम माणा, के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रविवार देर रात वह किसी दुकान से सामान लेने के लिए निकला था। इसी दौरान वह सड़क किनारे अचेत अवस्था में पड़ा मिला।घटना की सूचना मिलते ही टोल प्लाजा के अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे और धर्मेंद्र को तत्काल सुसनेर सिविल अस्पताल ले गए। वहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।सूचना मिलने पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और प्रारंभिक जांच के बाद मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया। सोमवार को शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है और मामले की जांच जारी है।

कलेक्टर ने समय-सीमा बैठक में की विभागों के कार्यों की गहन समीक्षा

राजगढ़। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के कलेक्टर डॉ. गिरीशकुमार मिश्रा ने सोमवार को आयोजित समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के निर्देश दिए। बैठक में स्वच्छता एवं वृक्षारोपण अभियान, जनकल्याण शिविरों की तैयारियां, पेयजल व्यवस्था, प्राकृतिक खेती, निर्माण कार्यों की प्रगति तथा लंबित शिकायतों की समीक्षा की गई।

जनकल्याण शिविरों की तैयारियों की समीक्षा के दौरान आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर पीओ डूडा, जल निगम, पीएचई, स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी विभागों को अपनी विस्तृत कार्ययोजना सोमवार शाम तक प्रस्तुत करने को कहा गया। कलेक्टर ने जिले में स्वच्छता और वृक्षारोपण कार्यक्रमों के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने तथा जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। छात्रावासों, विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों और शासकीय कार्यालयों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाने पर जोर दिया गया। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए उप संचालक कृषि को जनकल्याण शिविरों के माध्यम से प्रतिदिन 20 क्लस्टरों में जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए गए। वहीं 50 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों के शीघ्र निराकरण के आदेश भी दिए गए।

सार्थक अटेंडेंस ऐप की समीक्षा में मुख्यालय से उपस्थिति दर्ज नहीं करने के मामले में सारंगपुर के कंप्यूटर ऑपरेटर गोविंद शिवहरे के दो दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए। पेयजल संबंधी शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता से निराकृत करने के निर्देश देते हुए कलेक्टर ने कहा कि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। बैठक में निर्माण कार्यों, खाद्य विभाग के प्रकरणों, पीलूखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगों की जल-विद्युत खपत तथा हितग्राहीमूलक योजनाओं के भौतिक सत्यापन की भी समीक्षा की गई।

विदिशा के पोषण संजीवनी अभियान ने पेश की राज्य स्तरीय मिसाल

भोपाल। मध्य प्रदेश को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए निरंतर अभिनव और नीतिगत प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में विदिशा जिले से सफलता की एक ऐसी गौरवशाली गाथा सामने आई है, जिसने पूरे राज्य के सामने प्रशासनिक सूझबूझ और जनभागीदारी का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। जनसम्पर्क अधिकारी बिन्दु सुनील ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के 'स्वस्थ मध्य प्रदेश' के संकल्पों को जमीनी धरातल पर उतारते हुए विदिशा जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए 'पोषण संजीवनी अभियान' ने गंभीर कुपोषण के खिलाफ एक निर्णायक और प्रभावी जंग छेड़ दी है। यह अभियान इस बात का जीवंत प्रमाण बन गया है कि जब जिला प्रशासन और समाज की संवेदनशील ताकतें एक साथ कदम बढ़ाती हैं, तो कठिन से कठिन सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का समाधान सहज संभव हो जाता है। उन्होंने बताया कि अमूमन यह देखा जाता है कि पोषण पुनर्वास केंद्रों (एनआरसी) में उपचार के बाद जब बच्चे घर लौटते हैं, तो परिवारों की सीमित आर्थिक क्षमता और माताओं में पोषण संबंधी जागरूकता की कमी के कारण वे दोबारा कुपोषण चक्र में फंस जाते हैं। जून 2025 में हुए एक व्यापक सर्वे के दौरान विदिशा जिले में 1,307 गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान होने पर समस्या

की गंभीरता और स्पष्ट हो गई। इसी चुनौती को एक बड़े अवसर में बदलते हुए जिला कलेक्टर अंशुल गुप्ता के नेतृत्व में 'पोषण संजीवनी अभियान' की परिकल्पना की गई, जिसका मूल ध्येय बच्चों का तात्कालिक उपचार नहीं बल्कि उनका दीर्घकालिक सुपोषण सुनिश्चित करना था। जनसम्पर्क अधिकारी ने बताया कि अभियान के तहत प्रत्येक चिन्हित गंभीर कुपोषित बच्चे को तीन महीने तक अतिरिक्त पोषण देने के लिए 3000 रुपये मूल्य की विशेष 'सुपोषण किट' प्रदान की जा रही है। उच्च गुणवत्तायुक्त पौष्टिक तत्वों से भरपूर इस किट में दो किलो मूंगदाल, एक किलो बेसन, पंद्रह सौ ग्राम मुरमुरा, एक लीटर खाद्य तेल, एक किलो शुद्ध घी, डेढ़ किलो मूंगफली, एक किलो गुड़ पाउडर, दो किलो मल्टीग्रेन आटा, एक किलो सत्तू, दो किलो चावल और पांच सौ ग्राम तिल जैसी अत्यंत पौष्टिक सामग्रियां शामिल की गई हैं। यह संतुलित आहार बच्चों को प्रतिदिन लगभग 750 अतिरिक्त कैलोरी प्रदान करता है, जो उनके शारीरिक विकास के लिए संजीवनी साबित हो रहा है।उन्होंने बताया कि इस पूरे अभियान की सफलता के पीछे जनभागीदारी एक प्रमुख कारण बना। इस पुनीत कार्य में समाज के विभिन्न वर्गों, स्थानीय व्यापारियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने अभूतपूर्व संवेदनशीलता का परिचय दिया। समाज के सामूहिक प्रयासों से देखते ही देखते 39.21 लाख रुपये की सम्मानजनक राशि स्वेच्छा से एकत्र हो गई, जिसके माध्यम से अब तक सभी 1,307 बच्चों तक सुपोषण किट पहुंचाई जा चुकी है।

इस जनसहयोग ने यह सिद्ध कर दिया कि समाज अपने नौनिहालों के स्वास्थ्य के प्रति सजग है।जनसम्पर्क अधिकारी के अनुसार, प्रशासन ने केवल राशन वितरण तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि माताओं के व्यवहार में स्थायी बदलाव लाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के जमीनी अमले को पूरी मुस्तैदी से काम पर लगाया। आंगनवाड़ी कार्यकताओं द्वारा माताओं को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्रियों से सरल और पौष्टिक व्यंजन जैसे लड्डू, हलवा और सत्तू पेय बनाने की विधियों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और आनंद को ध्यान में रखते हुए उन्हें खिलौना किट और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए टिफिन व पानी की बोतलें भी उपहार स्वरूप दी गईं। तकनीक और कड़े पर्यवेक्षण के मोर्चे पर भी यह मॉडल बेहद सुदृढ़ है। 'पोषण ट्रैकर' ऐप के माध्यम से प्रत्येक बच्चे के चयन से लेकर उसकी शारीरिक प्रगति का संपूर्ण डिजिटल रिकॉर्ड संधारित किया जा रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकताओं द्वारा नियमित रूप से घर-घर जाकर बच्चों की वृद्धि निगरानी की गई। वहीं विभाग के पर्यवेक्षक लगातार बच्चों का वजन मापकर उनकी वास्तविक स्थिति का जमीनी आकलन कर रहे हैं।उन्होंने बताया कि इस बेहद सुनियोजित और समन्वित प्रयास के जो परिणाम निकलकर आए हैं, वे राज्य स्तर पर बेहद उत्साहजनक और प्रेरणादायी हैं। जिले के कुल 1,307 कुपोषित बच्चों में से 772 बच्चे पूरी तरह स्वस्थ होकर सामान्य श्रेणी में आ चुके हैं, जिससे 63.02% की उल्लेखनीय और ऐतिहासिक रिकवरी दर दर्ज की गई है। यह शानदार सफलता इस अभियान को प्रदेश के अन्य जिलों के लिए भी एक अनुकरणीय 'रोल मॉडल' के रूप में स्थापित करती है। यह अभियान अब एक प्रशासनिक पहल से आगे बढ़कर विदिशा में एक व्यापक जन-आंदोलन का रूप ले चुका है। जिला प्रशासन के सशक्त नेतृत्व में अब स्वयंसेवी संस्थाओं, प्रबुद्ध समाज सेवियों एवं विभिन्न सरकारी विभागों की सक्रिय अंतर-विभागीय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। विभाग द्वारा इन गंभीर कुपोषित बच्चों की सतत और गहन निगरानी की जा रही है ताकि परिवर्तन केवल कागजी आंकड़ों तक सीमित न रहे, बल्कि हर बच्चे के स्वस्थ भविष्य के संकल्प में बदले।

इंडोनेशिया की निशानेबाजी टीम ने भारत में तीन माह का उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण शिविर पूरा किया

नई दिल्ली। भारत की उभरती वैश्विक खेल प्रशिक्षण क्षमता को और मजबूती देते हुए गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन ने हाल ही में इंडोनेशिया की 16 सदस्यीय निशानेबाजी टीम और दो प्रशिक्षकों की मेजबानी की। यह तीन महीने का उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण शिविर पुणे और हैदराबाद स्थित प्रशिक्षण केंद्रों में आयोजित किया गया।

15 फरवरी से 15 मई तक चले इस प्रशिक्षण शिविर में इंडोनेशिया के कई प्रमुख निशानेबाजों ने हिस्सा लिया। इनमें लंदन 2012 ओलंपिक में भाग लेने वाली डियाज कुसुमावदार्नी और टोक्यो 2020 ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली विद्या रफिका रहमत्तान तोय्यिबा भी शामिल रहीं। दल में ऐसे खिलाड़ी भी मौजूद थे जो एशियाई खेल आइची-नागोया 2026 के लिए चयन की दौड़ में शामिल हैं।

शिविर के दौरान इंडोनेशियाई खिलाड़ियों ने भारत के शीर्ष निशानेबाजों के साथ अभ्यास किया और प्रतिस्पर्धात्मक प्रशिक्षण वातावरण का अनुभव प्राप्त किया। खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाओं, खेल विज्ञान सहायता, उन्नत प्रदर्शन विश्लेषण तकनीक और अनुभवी प्रशिक्षण दल का लाभ मिला। दल ने खेलो इंडिया निशानेबाजी प्रतियोगिता- 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह स्मृति निशानेबाजी प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया। भारत की प्रतिष्ठित घरेलू प्रतियोगिताओं में शामिल इस आयोजन ने खिलाड़ियों को मजबूत प्रतिस्पर्धा के बीच मुकाबले का अनुभव दिया। गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन के संस्थापक गगन नारंग ने कहा कि उच्च प्रदर्शन खेलों में सहयोग, अनुभव साझा करना और अलग-अलग प्रशिक्षण वातावरण बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने कहा कि उनके केंद्रों में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों का प्रशिक्षण लेना इस खेल तंत्र की गुणवत्ता को दर्शाता है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे अंतरराष्ट्रीय आदान-प्रदान कार्यक्रम केवल विदेशी खिलाड़ियों के लिए ही नहीं, बल्कि भारतीय खिलाड़ियों के लिए भी लाभकारी होते हैं और उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के सकारात्मक परिणामों के बाद इंडोनेशिया निशानेबाजी संघ और गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन भविष्य में भी संयुक्त प्रशिक्षण शिविर और सहयोगी कार्यक्रमों की संभावनाओं पर काम करने की तैयारी कर रहे हैं।

अल्टीमेट टेबल टेनिस का 7वां सीजन नौ जुलाई से, गोवा करेगा मेजबानी

गोवा। अल्टीमेट टेबल टेनिस के सातवें सत्र का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। प्रतियोगिता की शुरूआत 9 जुलाई से गोवा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में होगी। उद्घाटन मुकाबले में गत विजेता यू मुंबई टेबल टेनिस टीम का सामना मेजबान और दो बार की विजेता डेम्पो गोवा चैलेंजर्स से होगा। सात टीमों वाली यह प्रतियोगिता 26 जुलाई तक चलेगी। लीग चरण में सभी टीमें एक-दूसरे से एक बार भिड़ेंगी। अंक तालिका में शीर्ष चार स्थान हासिल करने वाली टीमें 24 और 25 जुलाई को होने वाले सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी, जबकि फाइनल मुकाबला 26 जुलाई को खेला जाएगा।

10 जुलाई को दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में यूपी प्रोमेथियंस की टक्कर दबंग दिल्ली से होगी, जबकि दूसरे मुकाबले में कोलकाता थंडरब्लेड्स का सामना पीबीजी पुणे जगुआर्स से होगा। अहमदाबाद एपीएल पाइपर्स अपने अभियान की शुरूआत 11 जुलाई को यू मुंबई के खिलाफ करेगा। लीग चरण में कई बड़े मुकाबले भी देखने को मिलेंगे। 16 जुलाई को महाराष्ट्र की दोनों टीमें यू मुंबई और पीबीजी पुणे आमने-सामने होंगी, जबकि 17 जुलाई को वर्ष 2024 के फाइनल की पुनरावृत्ति होगी, जिसमें डेम्पो गोवा और दबंग दिल्ली की भिड़ंत होगी।

पूरा कार्यक्रम, 9 जुलाई शाम 7:30 बजे – डेम्पो गोवा बनाम यू मुंबई 10 जुलाई, शाम 5:00 बजे – दबंग दिल्ली बनाम यूपी प्रोमेथियंस शाम 7:30 बजे – कोलकाता बनाम पीबीजी पुणे, 11 जुलाई शाम 5:00 बजे – दबंग दिल्ली बनाम कोलकाता, शाम 7:30 बजे – अहमदाबाद बनाम यू मुंबई, 12 जुलाई, शाम 5:00 बजे – यूपी प्रोमेथियंस बनाम पीबीजी पुणे शाम 7:30 बजे – अहमदाबाद बनाम डेम्पो गोवा, 13 जुलाई, शाम 7:30 बजे – डेम्पो गोवा बनाम कोलकाता, 14 जुलाई, शाम 7:30 बजे – अहमदाबाद बनाम यूपी प्रोमेथियंस, 15 जुलाई, शाम 7:30 बजे – दबंग दिल्ली बनाम यू मुंबई, 16 जुलाई

शाम 7:30 बजे – यू मुंबई बनाम पीबीजी पुणे, 17 जुलाई

शाम 5:00 बजे – अहमदाबाद बनाम कोलकाता, शाम 7:30 बजे – दबंग दिल्ली बनाम डेम्पो गोवा, 18 जुलाई, शाम 5:00 बजे – अहमदाबाद बनाम पीबीजी पुणे

शाम 7:30 बजे – यूपी प्रोमेथियंस बनाम यू मुंबई, 19 जुलाई, शाम 5:00 बजे – डेम्पो गोवा बनाम पीबीजी पुणे, शाम 7:30 बजे – कोलकाता बनाम यूपी प्रोमेथियंस 20 जुलाई, शाम 7:30 बजे – अहमदाबाद बनाम दबंग दिल्ली, 21 जुलाई शाम 7:30 बजे – कोलकाता बनाम यू मुंबई, 22 जुलाई शाम 7:30 बजे – डेम्पो गोवा बनाम यूपी प्रोमेथियंस 23 जुलाई, शाम 7:30 बजे – दबंग दिल्ली बनाम पीबीजी पुणे 24 जुलाई, शाम 7:30 बजे – पहला स्थान बनाम चौथा स्थान (सेमीफाइनल)

महिला टी-20 विश्व कप के लिए आईसीसी ने घोषित की विश्वस्तरीय कमेंट्री टीम

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने महिला टी-20 विश्व कप के लिए विश्वस्तरीय कमेंट्री टीम की घोषणा कर दी है। इस बार कमेंट्री पैनल में महिलाओं की प्रमुख भूमिका देखने को मिलेगी, जिसमें विश्व कप विजेता खिलाड़ी, पूर्व अंतरराष्ट्रीय कप्तान, अनुभवी प्रसारक और क्रिकेट जगत की कई प्रतिष्ठित आवाजें शामिल हैं। महिला टी-20 विश्व कप का आयोजन 12 जून से शुरू होगा, जिसमें उद्घाटन मुकाबला इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। प्रतियोगिता का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स मैदान पर होगा। पूरे टूर्नामेंट के दौरान कुल 33 मुकाबलों का प्रसारण किया जाएगा।

कमेंट्री टीम में कई ऐसे नाम शामिल हैं, जिन्होंने आईसीसी विश्व कप जीतने का अनुभव हासिल किया है। ऑस्ट्रेलिया की विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहीं मेल जोन्स और जूलिया प्राइस इस पैनल में शामिल हैं। वेस्टइंडीज की पूर्व खिलाड़ी स्टेसी-ऐन किंग भी टीम का हिस्सा हैं, जिन्होंने महिला टी-20 विश्व कप जीता था।

इंग्लैंड की विश्व कप विजेता टीम की सदस्य रहीं ईसा गुहा और एबोनी रेनफोर्ड-ब्रेंट भी कमेंट्री करेंगी। दोनों वर्ष 2009 में आयोजित पहले महिला टी-20 विश्व कप विजेता इंग्लैंड टीम का हिस्सा भी रही थीं।

पुरुष क्रिकेट से भी कई बड़े नाम इस टीम में शामिल किए गए हैं। दो बार पुरुष विश्व कप जीतने वाले मैथ्यू हेडन, भारत के पूर्व खिलाड़ी दिनेश कार्तिक और वेस्टइंडीज के पूर्व खिलाड़ी कार्लोस ब्रैथवेट भी कमेंट्री पैनल का हिस्सा होंगे। इसके अलावा क्रिकेट प्रसारण की दुनिया की चर्चित आवाजें नासिर हुसैन, इयान बिशप और इयान स्मिथ भी इस टूर्नामेंट में एक साथ नजर आएँगे। इन तीनों ने वर्ष 2019 पुरुष विश्व कप फाइनल के दौरान भी यादगार कमेंट्री की थी। कमेंट्री टीम में पूर्व कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी मिताली राज, ताश फेरेंट, अंजुम चोपड़ा, साइमन डूल, वेदा कृष्णमूर्ति, सना मीर, इसोबेल जॉयस और केटी मार्टिन भी शामिल हैं। प्रस्तुतकताओं और प्रसारण विशेषज्ञों की सूची में चार्ल्स डैगनॉल, नेटली जमानीस, एलन विल्किंस, लॉरा मैकगोल्ड्रिक, जतिन सप्रू, कैस नायडू, रौनक कपूर और अली मिशेल जैसे नाम शामिल हैं।

मानव सुथार के ऐतिहासिक छह विकेट, अफगानिस्तान 152 पर ढेर

न्यू चंडीगढ़। बाएं हाथ के युवा स्पिनर मानव सुथार ने अपने पदार्पण मुकाबले में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 6 विकेट झटके और अफगानिस्तान की पहली पारी को 152 रन पर समेटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत ने पहली पारी में 412 रन की विशाल बढ़त हासिल करने के बाद अफगानिस्तान को फॉलोऑन देने का फैसला किया।

महाराजा यादविंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर में खेले जा रहे एकमात्र मुकाबले में मानव सुथार ने 33 रन देकर 6 विकेट लिए। इसके साथ ही वह पदार्पण मुकाबले में किसी भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले गेंदबाज बन गए। उन्होंने 46 वर्ष पुराना दिलीप दोशी का रिकॉर्ड तोड़ा।

दोशी ने वर्ष 1979 में चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पदार्पण मुकाबले में 103 रन देकर 6 विकेट लिए थे।

तीसरे दिन अफगानिस्तान ने 5 विकेट पर 113 रन से आगे खेलना शुरू किया। रहमत शाह और अजमतुल्लाह उमरजई ने संभलकर शुरूआत की, लेकिन भारत ने जल्द ही दबाव बना लिया। प्रसिद्ध कृष्णा ने दिन की पहली सफलता दिलाई और उमरजई को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। रहमत शाह ने 100 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और वह अफगानिस्तान की ओर से पचास रन बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज रहे। इसके बाद मानव सुथार ने लगातार झटके दिए। उन्होंने शराफुद्दीन अशरफ को विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच कराया। अगले ही ओवर में रहमत शाह और सलीम सफी को भी आउट कर अफगानिस्तान की वापसी की उम्मीद खत्म कर दी।

जियाउर रहमान शरीफी ने मैदान पर आते ही छक्का लगाया, लेकिन वाशिंगटन सुंदर ने उनका विकेट लेकर अफगानिस्तान की पारी समाप्त कर दी। भारत की ओर से मानव सुथार ने 6 विकेट लिए, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा को 3 विकेट मिले। वाशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट हासिल किया।

मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव को कोई सफलता नहीं मिली। अफगानिस्तान की ओर से अब्दुल मलिक, सदीकुल्लाह अताल, रहमानुल्लाह गुरबाज और कप्तान हश्मतुल्लाह शाहिदी ने अच्छी शुरूआत की, लेकिन कोई भी बड़ी पारी नहीं खेल सका।

अर्थव्यवस्था

पूंजी बाजार घरेलू बचत और संपत्ति सृजन का प्रमुख जरिया बन रहे : तुहिन कांत पांडेय

मुंबई। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने सोमवार को कहा कि भारत में पूंजी बाजार घरेलू बचत और संपत्ति सृजन का प्रमुख माध्यम बनते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह इस बात का संकेत है कि निवेश के तरीकों में एक संरचनात्मक बदलाव आया है, जिससे लोग तेजी से बाजार आधारित विकल्पों की ओर बढ़ रहे हैं। तुहिन कांत पांडेय ने यहां 'आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज इंडिया इंवेस्टर कॉन्फ्रेंस 2026' को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने बताया कि भारत के कैपिटल मार्केट परिवारों की बचत और संपत्ति बनाने का एक अहम जरिया बनते जा रहे हैं। पांडेय ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में इक्विटी इश्यू 4.5 लाख करोड़ रुपये और कॉर्पोरेट बॉन्ड इश्यू 9 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गए हैं। सेबी के चेयरमैन ने कहा कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज (पीएमएस) के नियमों पर उन्होंने संकेत दिया कि इस पर व्यापक विचार-विमर्श जारी है और जल्द ही एक परामर्श पत्र जारी किया जाएगा। हालांकि उन्होंने कोई समयसीमा बताने से इनकार किया। पांडेय ने कहा कि भारत की आर्थिक प्रगति केवल ऊंची वृद्धि दर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अर्थव्यवस्था का औपचारिककरण, बचत का वित्तीयकरण और संस्थानों पर बढ़ता भरोसा भी शामिल है।

उन्होंने कहा कि भारतीय बाजारों की गहराई बढ़ रही है और अब देश में प्रतिभूति बाजार में लगभग 14.5 करोड़ निवेशक हैं। इनकी संख्या हर साल 20 फीसदी से अधिक की दर से बढ़ रही है। सेबी प्रमुख ने बताया कि म्यूचुअल फंड संपत्ति करीब 12 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 80 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई है, जबकि पूंजी बाजार में घरेलू

भागीदारी लगातार बढ़ रही है। पांडेय ने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में घरेलू वित्तीय बचत का हिस्सा वित्त वर्ष 2022-23 के लगभग 20 फीसदी से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 21.7 फीसदी हो गया है, जो विभिन्न वित्तीय साधनों में व्यापक भागीदारी के कारण संभव हुआ है। उन्होंने कहा, "ये सभी घटनाक्रम एक स्पष्ट बदलाव की ओर इशारा करते हैं" और अब घरेलू बचत का बड़ा हिस्सा बाजार-आधारित निवेश विकल्पों में जा रहा है।

उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में इक्विटी निर्गम 4.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि 366 आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिये लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपये जुटाए गए। कॉरपोरेट बॉन्ड निर्गम नौ लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा, जो पूंजी निर्माण में बाजारों की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। सेबी प्रमुख ने कहा कि पूंजी बाजार, घरेलू बचत और संपत्ति सृजन का एक प्रमुख माध्यम बनते जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बाजार पूंजीकरण जीडीपी के लगभग 69 प्रतिशत (एक दशक पहले) से बढ़कर अब करीब 128 प्रतिशत हो गया है। पांडेय ने कहा कि निवेशकों की बढ़ती संख्या के साथ नियामकों और बाजार मध्यस्थों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि वे पारदर्शिता, निवेशक संरक्षण तथा बाजार की निष्पक्षता सुनिश्चित करें।

निवेशकों की भूमिका पर जोर देते हुए पांडेय ने कहा कि हर नियामकीय सुधार और बाजार पहल का अंतिम उद्देश्य निवेशकों का भरोसा मजबूत करना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि निवेशक को सूचित, संरक्षित तथा निष्पक्ष व्यवहार का अनुभव होता है तो विश्वास बढ़ेगा, भागीदारी गहरी होगी और बाजार एक मजबूत एवं टिकाऊ आधार पर लगातार बढ़ते रहेंगे।

देश में 58 करोड़ जन धन खातों से करोड़ों लोग औपचारिक बैंकिंग से जुड़े : वित्त मंत्री

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि 58 करोड़ से ज्यादा जन धन खातों ने करोड़ों भारतीयों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा। इस विस्तार ने वित्तीय समावेश को बढ़ावा दिया है। साथ ही सुनिश्चित हुआ है कि कल्याणकारी लाभ और पेंशन बिना किसी लीकेज के सीधे नागरिकों तक पहुंचें। वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जन-धन योजना के तहत कल्याणकारी योजनाओं, कम लागत वाले बीमा और पेंशन के लाभ सीधे लोगों तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीबी और अभाव के खिलाफ लड़ाई में भारत वैश्विक स्तर पर अलग पहचान बना रहा है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरूआत 28 अगस्त, 2014 को की गई थी। यह दुनिया की सबसे

बड़ी वित्तीय समावेशन पहल में से एक है। इस योजना के तहत 56 फीसदी खाताधारक महिलाएं हैं। वहीं, 67 फीसदी खाते ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक जन-धन योजना ने लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ने में मदद की है, जिससे उनके जीवन में बदलाव आया है और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है।

मंत्रालय के मुताबिक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिये लाभार्थियों के खातों में लगभग 45 लाख करोड़ रुपये सीधे हस्तांतरित किए गए हैं। अब भारत की 94 फीसदी वयस्क आबादी के पास बैंक खाता है।

इस योजना के तहत खोले गए बैंक खातों में शून्य 'बैलेंस' की सुविधा, मुफ्त रुपे कार्ड, दुर्घटना बीमा और 'ओवरड्राफ्ट' की सुविधा मिलती है।

सर्राफा बाजार में मेरिट्रॉनिक्स लिमिटेड की धमाकेदार शुरूआत, पहले दिन ही डबल हुआ निवेशकों का पैसा

नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेरिट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में धमाकेदार एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को जबरदस्त मुनाफा करा दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 149 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर इसकी लिस्टिंग मैक्सिमम परमिटेड प्रीमियम लिमिट यानी 90 प्रतिशत प्रीमियम के साथ 283.10 रुपये के स्तर पर हुई। लिस्टिंग के बाद हुई लिवाली के कारण कंपनी के शेयर थोड़ी देर में ही उछल कर 297.25 रुपये के अपर सर्किट लेवल पर पहुंच गई। इस तरह पहले दिन के कारोबार में ही कंपनी के आईपीओ निवेशकों को प्रति शेयर 148.25 रुपये यानी 99.50 प्रतिशत का मुनाफा हो गया।

मेरिट्रॉनिक्स लिमिटेड का 70.03 करोड़ रुपये का आईपीओ एक से तीन जून के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से शानदार रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 315.36 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 224.91 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 476.59 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसी तरह रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 297.67 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 47 लाख नए शेयर जारी किए गए हैं। आईपीओ के जरिये जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल मशीनरी और इक्विपमेंट्स की खरीदारी करने, पुराने कर्ज को कम करने, वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी।

मेरिट्रॉनिक्स लिमिटेड की वित्तीय स्थिति की बात करें तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास जमा कराए गए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी को 3.05 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 8.66 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इसके बाद पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का शुद्ध लाभ उछल कर 16.10 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया।

इस दौरान कंपनी की राजस्व प्राप्ति में भी लगातार बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2023-24 में इसे 86.01 करोड़ का कुल राजस्व प्राप्त हुआ, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 114.04 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी को 156.25 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। इस अवधि में कंपनी पर लदे कर्ज का बोझ भी लगातार बढ़ता गया। वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में कंपनी पर 15.82 करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ था, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 18.57 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। वहीं पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की बात करें, तो इस दौरान कंपनी पर लदे कर्ज का बोझ 43.20 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। इस अवधि में कंपनी के नेटवर्थ में भी बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2023-24 में ये 7.58 करोड़ रुपये के स्तर पर था, जो 2024-25 में बढ़ कर 16.23 करोड़ रुपये हो गया। वहीं पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की बात करें, तो इस दौरान कंपनी का नेटवर्थ जोरदार उछाल के साथ 52.52 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

कंपनी के रिजर्व और सरप्लस की बात करें, तो इस अवधि में कंपनी इस मोर्चे पर भी बढ़त हासिल करने में सफल रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में ये 6.73 करोड़ रुपये के स्तर पर था, जो 2024-25 में बढ़ कर 15.39 करोड़ रुपये हो गया।

इसी तरह पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का रिजर्व और सरप्लस 40.34 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया था। इसी तरह ईबीआईटीडीए (अर्निंग बिफोर इंट्रेस्ट, टैक्सेज, डिप्रेशिएशंस एंड एमॉर्टाइजेशन) 2023-24 में 6.73 करोड़ रुपये के स्तर पर था, जो 2024-25 में बढ़ कर 15.18 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। वहीं पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की बात करें, तो इस दौरान कंपनी का ईबीआईटीडीए 27.22 करोड़ रुपये के स्तर पर था।

कच्चे तेल की कीमत से झुलसा शेयर बाजार, बड़ी गिरावट के साथ सेंसेक्स-निफ्टी बंद

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ रहे तनाव और कच्चे तेल की कीमत में आई तेजी के कारण घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट का शिकार हो गया। आज के कारोबार की शुरूआत भी कमजोरी के साथ हुई थी। हालांकि दिन के पहले सत्र में निचले स्तर पर हुई वैल्यू बाइंग के कारण शेयर बाजार की स्थिति में काफी हद तक सुधार भी हुआ, लेकिन दोपहर एक बजे के करीब बाजार में दोबारा बिकवाली का दबाव बन गया, जिसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों की कमजोरी बढ़ती चली गई।

पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स 0.97 प्रतिशत और निफ्टी 1.04 प्रतिशत की कमजोरी के साथ बंद हुए। आज दिन भर सभी सेक्टर पर दबाव बना रहा। दिन भर हुई बिकवाली के कारण सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। रियल्टी और मेटल सेक्टर के शेयरों में आज जम कर बिकवाली होती रही, जिसके कारण निफ्टी का मेटल इंडेक्स 2.43 प्रतिशत की कमजोरी के साथ बंद हुआ।